



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414]
No. 414]

नई दिल्ली, बुध्दस्पतिवार, सितम्बर 13, 2007/भाद्र 22, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2007/BHADRA 22, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2007

सं. 94/2007-सीमा शुल्क (मै. टै.)

सा.का.नि. 592(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के साथ पठित धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल का मूल्य निर्धारण) नियमावली, 1988 के अधिक्रान्त में, ऐसे अधिक्रान्त से पहले की गई अथवा विलोपित की गई बातों को छोड़कर, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्ष, आरंभ और लागू होना:- (1) इन नियमों को सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल का मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2007 कहा जाए।

(2) ये दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये आयातित माल के लिए लागू होंगे।

2. परिभाषाएं. - (1) इन नियमों में जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो, -

(क) 'संगठित मूल्य' का आशय नियम 8 के अनुसार निर्धारित आयातित माल के मूल्य से है।

(ख) 'निगमनात्मक मूल्य' का आशय नियम 7 के अनुसार निर्धारित मूल्य से है।

(ग) 'उसी वर्ग अथवा प्रकार के माल' का आशय आयातित माल से है जो किसी विशेष उद्योग अथवा औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित आयातित माल जिसमें समरूप माल अथवा उसी तरह का माल शामिल है, के समूह अथवा रेंज के भीतर है;

(घ) 'समरूप माल' का आशय आयातित माल -

- (i) जो वास्तविक विशेषताओं, गुणवत्ता और ख्याति सहित सभी तरह उसी प्रकार का है क्योंकि उक्त माल दिखावे में मामूली अन्तर को छोड़कर मूल्यांकित किया जा रहा है जो माल के मूल्य को प्रभावित नहीं करता है;
- (ii) उस देश में उत्पादित जिसमें मूल्यांकित किया गया माल उत्पादित किया गया था; और
- (iii) उसी व्यक्ति द्वारा उत्पादित जिसने माल का उत्पादन किया अथवा जहां ऐसा माल उपलब्ध नहीं है तो किसी भिन्न व्यक्ति द्वारा उत्पादित माल लेकिन इसमें आयातित माल शामिल नहीं होगा जहां भारत में किया गया अभियांत्रिकी, विकास कार्य, कला कार्य डिजाइन कार्य, योजना अथवा खाका कार्य इन आयातित माल पर क्रेता द्वारा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः पूरा किए गए कार्य इस आयातित माल के निर्यात के लिए उत्पादन और बिक्री के संबंध में उपयोग हेतु प्रभार से मुक्त थे अथवा उनकी लागत कम की गई थी;

(ङ) 'उत्पादित' में उगाया गया, विनिर्मित और खान से निकाला गया माल शामिल है

(च) 'समान माल' का आशय आयातित माल -

- (i) जो हालांकि सभी तरह से एक समान नहीं है, की समान विशेषताएं और समान संघटक सामग्री है जो उसे उसी तरह के कार्य के निष्पादन में समर्थ बनाती हैं और गुणवत्ता, ख्याति और ट्रेड मार्क के अस्तित्व के संबंध में मूल्यांकित किए जा रहे माल के साथ वाणिज्यिक तौर पर अन्तर परिवर्तनीय हो सकती है;

(ii) उस देश में उत्पादित जिसमें मूल्यांकित किया गया माल उत्पादित किया गया था; और

(iii) उसी व्यक्ति द्वारा उत्पादित जिसने माल का उत्पादन किया अथवा जहां ऐसा माल उपलब्ध नहीं है तो किसी भिन्न व्यक्ति द्वारा उत्पादित माल लेकिन इसमें आयातित माल शामिल नहीं होगा जहां भारत में किया गया अभियांत्रिकी, विकास कार्य, कला कार्य, डिजाइन कार्य, योजना अथवा खाका कार्य इन आयातित माल पर क्रेता द्वारा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः पूरा किए गए कार्य इस आयातित माल के निर्यात के लिए उत्पादन और बिक्री के सम्बन्ध में उपयोग हेतु प्रभार से मुक्त थे अथवा उनकी लागत कम की गई थी;

(छ) 'लेनदेन मूल्य' का आशय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उपधारा (1) में उल्लिखित मूल्य से है;

(2) इन नियमों के प्रयोजनार्थ व्यक्ति को केवल तभी 'सम्बद्ध' समझा जाएगा यदि -

- (i) वे एक दूसरे के कारोबार के अधिकारी अथवा निदेशक हैं;
- (ii) वे कारोबार में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त भागीदार हैं;
- (iii) वे नियोक्ता और कर्मचारी हैं;
- (iv) कोई व्यक्ति अशोधित वोटिंग स्टॉक अथवा शेयर दोनों का पांच प्रतिशत अथवा उससे अधिक का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामी है, नियंत्रण अथवा धारक है;
- (v) उनमें से एक दूसरे का प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः नियंत्रण करता है;
- (vi) दोनों किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः नियंत्रित हैं;
- (vii) वे साथ-साथ किसी तीसरे व्यक्ति को प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः नियंत्रण करते हैं; अथवा
- (viii) वे उसी परिवार के सदस्य हैं ।

स्पष्टीकरण I - 'व्यक्ति' शब्द में विधिक व्यक्ति भी शामिल हैं ।

स्पष्टीकरण II - व्यक्ति जो एक दूसरे के उस कारोबार में सहायक हैं जिसमें एक दूसरे का एक मात्र एजेंट अथवा एक माल वितरक अथवा एक मात्र ग्राही हो जो भी उल्लेख किया जाए, इन नियमों के प्रयोजनार्थ सम्बद्ध समझे जाएंगे। बशर्ते वे इस उपनियम में मानदंड के भीतर आते हों।

3. मूल्यांकन की पद्धति का निर्धारण:- (1) नियम 12 के विषय, आयातित माल का मूल्य नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार समायोजित लेनदेन मूल्य होगा;

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत आयातित माल के मूल्य को स्वीकार किया जाएगा :

बशर्ते कि

(क) प्रतिबंधों को छोड़कर क्रेता द्वारा माल के निपटान अथवा उपयोग के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है जो -

- (i) भारत में विधि द्वारा अथवा सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए हों अथवा अपेक्षित हो; अथवा
- (ii) भूगोलीय क्षेत्र में सीमित करता है जिसमें माल को पुनः बिक्री की जा सकती है; अथवा
- (iii) माल के मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रभावित नहीं करता है;

(ख) बिक्री अथवा मूल्य किसी शर्त अथवा प्रतिफल के अध्वधीन नहीं है जिसके लिए मूल्यांकित किए जा रहे माल के सम्बन्ध में कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता;

(ग) क्रेता द्वारा माल की किसी अनुवर्ती पुनः बिक्री, निपटान अथवा उपयोग के आगमों का कोई मात्र विक्रेता को प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रोद्भूत नहीं होगा जब तक इन नियमों के नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार कोई समुचित समायोजन नहीं किया जाता है; और

(घ) क्रेता और विक्रेता सम्बद्ध नहीं हैं अथवा जहां क्रेता और विक्रेता सम्बद्ध है तो वह लेनदेन मूल्य नीचे उपनियम (3) के प्रावधानों के अंतर्गत सीमा शुल्क के प्रयोजनों के लिए स्वीकार्य है ।

(3) (क) जहां क्रेता और विक्रेता सम्बद्ध है, लेनदेन मूल्य स्वीकार किया जाएगा बशर्ते कि आयातित माल की बिक्री की परिस्थितियों की जांच से जाहिर होता है कि सम्बद्धता मूल्य को प्रभावित नहीं करती।

(ख) सम्बद्ध व्यक्तियों के बीच किसी बिक्री में लेनदेन मूल्य को स्वीकार किया जाएगा जब कभी आयातक यह दर्शाये कि मूल्यांकन किए जा रहे माल का घोषित मूल्य उसी समय निर्धारित किए जा रहे निम्नलिखित में से एक मूल्य के निकटतम अथवा के लगभग है ।

- (i) भारत में असम्बद्ध क्रेताओं को बिक्री में समरूप माल अथवा समान के माल का लेनदेन मूल्य;
- (ii) समरूप माल अथवा समान माल के आनुमानिक मूल्य;
- (iii) समरूप माल अथवा समान माल के लिए संगठित मूल्य;

बशर्ते कि तुलना हेतु प्रयुक्त मूल्यों का अनुप्रयोग करने में शेष खाते को नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार वाणिज्यिक स्तरों, मात्रा के स्तरों, समायोजनों में प्रदर्शित अंतर और बिक्री में विक्रेता द्वारा वहन लागत जिसमें वह एवं क्रेता सम्बद्ध नहीं है, को शामिल किया जाएगा;

(ग) प्रतिस्थापित मूल्य इस नियम के खण्ड (ख) के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित नहीं किया जाएगा ।

(4) यदि उक्त मूल्य उपनियम (1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित नहीं किए जाते हैं तो मूल्य नियम 4 से 9 के माध्यम से आगामी अनुक्रम द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

4. समरूप माल का लेनदेन मूल्य. - (1)(क) नियम 3 के प्रावधानों के अध्यक्षीन आयातित माल का मूल्य भारत में निर्यात हेतु बेचे गए और आयातित अथवा उसी समय मूल्यांकित किए जा रहे माल के रूप में समरूप माल का लेनदेन मूल्य होगा;

बशर्ते कि ऐसा लेनदेन मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18 के अंतर्गत अस्थायी रूप से निर्धारित माल का मूल्य नहीं होगा ।

(ख) इस नियम के अनुप्रयोग में उसी वाणिज्यिक स्तर पर किसी बिक्री में और मूल्यांकित किए जा रहे माल के रूप में पर्याप्त रूप से उसी मात्रा में समरूप माल के लेनदेन मूल्य को आयातित माल के मूल्य के निर्धारण हेतु प्रयुक्त किया जाएगा ।

(ग) जहां उपनियम (1) के खण्ड (ख) में संदर्भित कोई बिक्री नहीं पाई जाती है, तो किसी भिन्न वाणिज्यिक स्तर पर अथवा भिन्न मात्रा में अथवा दोनों पर पर बेचे गए समरूप माल के वाणिज्यिक स्तर अथवा मात्रा अथवा दोनों के लिए आरोप्य अंतर को शामिल करने के लिए समायोजित लेनदेन मूल्य का उपयोग किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसे समायोजन प्रदर्शित साक्ष्य जो समायोजनों की युक्तिसंगतता और सत्यता को स्पष्टतः स्थापित करते हैं, चाहे ऐसे समायोजन मूल्य में वृद्धि अथवा कमी करते हो, के आधार पर किया जाए ।

(2) जहां इन नियमों के नियम 10 के उप नियम (2) में संदर्भित लागत और प्रभार को समरूप माल के लेनदेन मूल्य में शामिल किया जाता है, तो समायोजन किया जाएगा यदि मूल्यांकित किए जा रहे माल और प्रश्नगत समरूप माल के बीच दूरी और परिवहन के साधनों में अन्तर से प्रोद्भूत ऐसी लागतों और लागतों में काफी अंतर है ।

(3) इस विषय के अनुप्रयोग में यदि समरूप माल का एक से अधिक लेनदेन मूल्य पाया जाता है तो ऐसे मूल्य के निम्नतम मूल्य को आयातित माल के मूल्य के निर्धारण हेतु उपयोग किया जाएगा ।

5. समान माल का लेनदेन मूल्य. - (1) नियम 3 के प्रावधानों के अध्यक्षीन आयातित माल का मूल्य भारत में निर्यात हेतु बेचे गए और आयात किए गए

अथवा उसी समय के लगभग मूल्यांकित किए जा रहे माल के रूप में समान माल का लेनदेन मूल्य होगा;

नियम 18 बशर्ते कि ऐसा लेनदेन मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत अस्थायी रूप से निर्धारित माल का मूल्य नहीं होगा।

(2) नियम 4 के उप नियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (1) के खंड (ख) और (ग) के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित समान माल के संबंध में भी लागू होंगे।

6. जहां नियम 3, 4 और 5 के अंतर्गत मूल्य निर्धारित नहीं किए जा सकते वहां मूल्य का निर्धारण. - यदि आयातित माल का मूल्य नियम 3 और 5 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित नहीं किए जा सकते तो मूल्य नियम 7 के प्रावधानों अथवा जब मूल्य उक्त नियम के अंतर्गत निर्धारित नहीं किए जा सकते तो नियम 8 के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते कि आयातक के अनुरोध पर और सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से नियम 7 और 8 का अनुप्रयोग आदेश परिवर्तित हो जाएगा।

7. निगमनात्मक मूल्य. - (1) नियम 3 के प्रावधानों के अधीन यदि मूल्यांकित किया जा रहा माल अथवा समरूप अथवा समान आयातित माल को भारत में बेचा जाता है, उसी समय अथवा उसी के आस पास समय पर आयातित के रूप में शर्त के अनुसार जिस पर मूल्य के निर्धारण की घोषणा प्रस्तुत की जाती है तो आयातित माल का मूल्य उस यूनिट मूल्य पर आधारित होगा जिसपर आयातित माल अथवा समरूप अथवा समान आयातित माल काफी बड़ी मात्रा में उन व्यक्तियों को निम्नलिखित कटौतियों के अधीन बेचा जाता है जो भारत में विक्रेता से सम्बद्ध नहीं हैं :-

- (i) या तो उसी वर्ग अथवा प्रकार का आयातित माल भारत में बिक्री के सम्बन्ध में आमतौर पर कमीशन दिया जाता है अथवा देने हेतु सहमत होते हैं अथवा लाभों और सामान्य खर्चों के लिए आमतौर पर जोड़ा जाता है;
- (ii) भारत के भीतर की परिवहन और बीमा की सामान्य लागतें और सहायक लागतें;

(iii) माल के आयात अथवा बिक्री के कारण भारत में संदेय सीमा शुल्क और अन्य कर ।

(2) यदि न तो आयातित माल न ही समरूप न ही समरूप न ही समान आयातित माल मूल्यांकित किए जा रहे माल के आयात के समय पर अथवा उसके लगभग समय पर बेचा जाता है तो आयातित माल का मूल्य, उपनियम (1) प्रावधानों से अन्यथा अध्यधीन, उस यूनिट मूल्य पर आधारित होगी जिस पर आयात के पश्चात जल्दी से जल्दी तारीख को लेकिन ऐसे आयात के नब्बे दिन की समाप्ति से पहले आयातित माल अथवा समरूप अथवा समान आयातित माल को भारत में बेचा जाता है ।

(3)(क) यदि आयात करने की शर्त के रूप में न तो आयातित माल न ही समरूप न ही समान आयातित माल भारत में बेचा जाता है तो मूल्य उस यूनिट मूल्य पर आधारित होगा जिसपर आयातित माल आगे प्रसंस्करण के पश्चात काफी बड़ी मात्रा उन व्यक्तियों को बेचा जाता है जो भारत में विक्रेता से सम्बन्ध नहीं रखते हैं ।

(ख) ऐसे निर्धारण में देय अनुमति उपनियम(1) की मद (i) से (iii) तक में प्रावधान की गई प्रक्रिया और कटौतियों द्वारा जोड़े गए मूल्य के लिए दी जाएगी।

8. संगणित मूल्य- नियम 3 के प्रावधानों के मध्यधीन आयातित माल का मूल्य संगणित मूल्य पर आधारित होगा जिसमें निम्नलिखित राशि शामिल होगी:-

(क) आयातित माल के उत्पादन में काम में ली गई सामग्री और विनिर्माण अथवा अन्य प्रक्रिया की लागत अथवा मूल्य;

(ख) लाभ और सामान्य खर्च की उस राशि के बराबर राशि को आमतौर पर मूल्यांकित किए जा रहे माल के रूप में उसी वर्ग अथवा प्रकार के माल की बिक्रियों में दर्शाया जाता है जो भारत में निर्यात के लिए निर्यात करने वाले देश में विनिर्माताओं द्वारा बनाया जाता है;

(ग) नियम 10 के उपनियम (2) के अंतर्गत अन्य सभी खर्चों की लागत अथवा मूल्य।

9. अवशिष्ट पद्धति - (1) नियम 3 के प्रावधानों के अध्यक्षीन जहां आयातित माल का मूल्य किसी भी पूर्ववर्ती नियम के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित नहीं किया जा सकता तो मूल्य का निर्धारण इन नियमों के सिद्धांतों और सामान्य प्रावधानों के साथ संगत उचित साधनों का उपयोग करते हुए और भारत में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा;

बशर्ते कि ऐसा निर्धारित मूल्य उस मूल्य से अधिक नहीं होगा जिस पर ऐसा अथवा इसी तरह के माल के, जब विक्रेता अथवा क्रेता का अन्य के कारोबार में कोई हित नहीं है और बिक्री अथवा बिक्री के प्रस्ताव हेतु मूल्य ही एकमात्र प्रतिफल है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान आयात के और स्थान पर सुपुर्दगी के लिए सामान्यतया बेचा जाता है अथवा बेचने का प्रस्ताव किया गया हो।

(2) इस नियम के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित आधार पर कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जायेगा -

- (i) भारत में उत्पादित माल का भारत में बिक्री मूल्य;
- (ii) एक प्रणाली जो दो वैकल्पिक मूल्यों में उच्चतम मूल्य को सीमा शुल्क के प्रयोजनार्थ स्वीकार करने की व्यवस्था करती है;
- (iii) निर्यात करने वाले देश के घरेलू बाजार मूल्य पर माल का मूल्य;
- (iv) संगणित मूल्य को छोड़कर उत्पादन की लागत जो नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार समरूप अथवा समान माल के लिए निर्धारित की गई है;
- (v) भारत को छोड़कर अन्य किसी देश को निर्यात हेतु माल का मूल्य ;
- (vi) न्यूनतम सीमा शुल्क मूल्य ; अथवा
- (vii) मध्यवर्ती अथवा बराबरी मूल्य।

10. लागत और सेवाएं - (1) लेनदेन मूल्य में निर्धारण में आयातित माल के लिए वास्तव में संदत्त अथवा संदेय मूल्य को जोड़ा जायेगा,

(क) निम्नलिखित सीमा तक वे क्रेता द्वारा वहन की गई हैं लेकिन आयातित माल के लिए वास्तव में संदत्त अथवा संदेय मूल्य में शामिल नहीं किया जाता है, अर्थात:-

- (i) खरीद कमीशन को छोड़कर कमीशन और दलाली;
- (ii) कंटेनरों की लागत जो प्रश्नगत माल के साथ सीमाशुल्क एक प्रयोजन के रूप में माना जाता है;
- (iii) पैकिंग की लागत चाहे श्रम के लिए हो अथवा सामग्री के लिए हो;

(ख) समुचित भाग के अनुसार निम्नलिखित माल और सेवाओं का मूल्य जहां उस सीमा तक आयातित माल के निर्यात हेतु उत्पादन और बिक्री के संबंध में प्रभार से मुक्त अथवा कम की गई लागत पर क्रेता द्वारा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः पूर्ति की जाती है कि ऐसा मूल्य वास्तव में संदत्त अथवा संदेय मूल्य में शामिल नहीं किया जाता है, अर्थात:-

- (i) आयातित माल में शामिल सामग्री, पुर्जे और समान वस्तुएं;
- (ii) आयातित माल के उत्पादन में प्रयुक्त औजार, डाईज, मोल्ड और समान वस्तुएं;
- (iii) आयातित माल के उत्पादन में उपयोग की गई सामग्री;
- (iv) भारत को छोड़र अन्यत्र किए गए और आयातित माल के उत्पादन के लिए आवश्यक अभियांत्रिकी, विकास, आर्ट कार्य, डिजाइन कार्य और योजना एवं खाका;

(ग) आयातित माल से सम्बद्ध रायल्टियों और लाइसेंस फीस जो क्रेता को इस सीमा तक मूल्यांकित किए जा रहे माल की बिक्री की एक शर्त के रूप में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः संदत्त करनी अपेक्षित है कि ऐसा रायल्टियां और फीस को वास्तव में संदत्त अथवा संदेय मूल्य में शामिल नहीं किया जाता है:

(घ) आयातित माल की किसी अनुवर्ती पुनः बिक्री, निपटान अथवा उपयोग के आगमों के किसी भाग का मूल्य जो विक्रेता को प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रोद्भूत होते हों;

(ड.) क्रेता द्वारा विक्रेता को अथवा क्रेता द्वारा तीसरे पक्ष को उस सीमा तक विक्रेता के दायित्व को पूर्ति के लिए आयातित माल की बिक्री के एक शर्त के रूप में वास्तव में किए गए अथवा किए जाने वाले अन्य सभी भुगतान जिसमें ऐसे भुगतानों को वास्तव में संदत्त अथवा संदेय मूल्य में शामिल नहीं किया जाता है।

व्याख्या. - जहां किसी प्रक्रिया के लिए रायल्टी, लाइसेंस शुल्क अथवा कोई अन्य भुगतान चाहे पेटेंटेड हो अथवा नहीं, खंड (ग) और (ड.) के उल्लेख में शामिल किए जाने योग्य हों ऐसे प्रभार आयातित माल के लिए वास्तविक रूप में किए गए अथवा किए जाने योग्य भुगतान में जोड़े जाएंगे चाहे ऐसे माल आयात के बाद उक्त प्रक्रिया के अधीन ही क्यों न हो।

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (1) और इन-नियमों के उद्देश्य के लिए आयातित माल का मूल्य आयात के समय और स्थान पर प्रदान करने के लिए ऐसे माल के मूल्य के बराबर होगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होगा -

(क) आयातित माल के आयात स्थल तक के परिवहन की लागत;

(ख) आयात स्थल पर आयातित माल प्रदान करने से सम्बद्ध लदान, खाली करने तथा हैंडलिंग प्रभार; और

(ग) बीमा लागत :

बशर्ते कि -

- (i) जहां खंड (क) में उल्लिखित परिवहन लागत तय होने योग्य न हो, ऐसी लागत माल के पोत पर्यन्त निःशुल्क लागत का बीस प्रतिशत होगी;
- (ii) खंड (ख) में उल्लिखित प्रभार माल के पोत पर्यन्त निःशुल्क लागत का एक प्रतिशत और खंड (क) में उल्लिखित परिवहन लागत और खंड (ग) में उल्लिखित स्थित बीमा लागत होगी;
- (iii) जहां खंड (ग) में उल्लिखित लागत तय होने योग्य न हो, ऐसी लागत माल के पोत पर्यन्त निःशुल्क लागत का 1.125% होगी;

साथ ही बशर्ते कि विमान से आयातित माल के मामले में जहां खंड (क) में उल्लिखित लागत तय होने योग्य न हो, ऐसी लागत माल के पोत पर्यन्त निःशुल्क लागत के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते कि माल के पोतपर्यन्त निःशुल्क लागत तय हाने योग्य न हो, खंड (क) में उल्लिखित लागत माल के पोतपर्यन्त निःशुल्क लागत का बीस प्रतिशत होगी और उपर्युक्त खंड (i) के लिए बीमा लागत तथा खंड (ग) में उल्लिखित लागत माल के पोतपर्यन्त निःशुल्क लागत का 1.125% एवं उपर्युक्त खंड (iii) के लिए परिवहन लागत होगी ।

बशर्ते कि इनलैंड कंटेनर डिपो अथवा कंटेनर फ्रेट स्टेशन पर निकासी हेतु कंटेनर में भरकर समुद्रीय रास्ते से आयातित माल के मामले में प्रविष्टि वाले पोर्ट से इनलैंड कंटेनर डिपो अथवा कंटेनर फ्रेट स्टेशन तक लाने में खर्च किए गए भाड़े की लागत को खंड (क) में उल्लिखित परिवहन लागत में शामिल नहीं किया जाएगा ।

व्याख्या - खंड (क) में उल्लिखित आयातित माल के परिवहन की लागत में चार्टर्ड पोतों पर पोत विलम्ब शुल्क, लाइटरेज व चार्ज प्रभार शामिल हैं ।

(3) इस नियम के अंतर्गत निष्पक्ष और परिमाण बताने योग्य आंकड़ों के आधार पर वास्तव में किए गए भुगतान अथवा देय मूल्य में योग किया जाएगा ।

(4) इस नियम में किए गए प्रावधान को छोड़कर आयातित माल का मूल्य निर्धारित करने में वास्तव में किए गए भुगतान अथवा देय मूल्य में कोई योग नहीं किया जाएगा ।

11. आयातक द्वारा घोषणा. - (1) आयातक अथवा उसका एजेन्ट निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा -

(क) आयातित माल के मूल्य से संबंधित पूर्ण और सही विवरणों की घोषणा; और

(ख) जहां माल का आयात निर्माता अथवा उत्पादन को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से अथवा के माध्यम से किया जाता है वहां आयातित माल के निर्माता अथवा उत्पादक के बीजक सहित इन नियमों के अंतर्गत आयातित माल के मूल्य निर्धारण के लिए उपयुक्त अधिकारी द्वारा मांगा गया कोई अन्य विवरण, सूचना अथवा दस्तावेज ।

(2) इन नियमों में अन्तर्निहित कोई भी तथ्य सीमा शुल्क के उपयुक्त अधिकारी द्वारा मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत किसी विवरण, सूचना, दस्तावेज अथवा घोषणा की सत्यता अथवा प्रामाणिकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के अधिकार पर प्रतिबंध अथवा प्रश्न-चिन्ह नहीं समझा जाएगा ।

(3) जब्ती, अर्थदंड और अभियोजन के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के प्रावधान ऐसे मामलों में लागू होंगे जहां इन नियमों के अंतर्गत गलत घोषण, सूचना, विवरण अथवा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हों।

12. घोषित मूल्य की अस्वीकृति—(1) जब उपयुक्त अधिकारी के पास किसी आयातित माल के संबंध में घोषित मूल्य की सत्यता अथवा प्रामाणिकता पर संदेह करने का कारण हो तो वे ऐसे माल के आयातक से दस्तावेज अथवा अन्य साक्ष्य सहित और सूचना प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी अन्य सूचना प्राप्त होने के बाद भी अथवा ऐसे आयातक का जवाब नहीं मिलने पर घोषित मूल्य की सत्यता अथवा प्रामाणिकता पर संदेह का कारण मौजूद हो यह समझा जाएगा कि ऐसी आयातित माल के कारोबार मूल्य का निर्धारण नियम 3 के उप नियम (1) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं हो सकता है।

(2) आयातक के अनुरोध पर उपयुक्त अधिकारी ऐसे आयातक द्वारा आयातित माल के संबंध में घोषित मूल्य की सत्यता और प्रामाणिकता पर संदेह करने का कारणों के संबंध में आयातक को लिखित सूचित करेंगे और उप नियम (1) के अंतर्गत अंतिम निर्णय लेने से पूर्व सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेंगे।

व्याख्या—(1) संदेहों को दूर करने के लिए एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि—

- (i) यह नियम स्वयं ही मूल्य निर्धारण के लिए पद्धति प्रदान नहीं करता है, बल्कि यह ऐसे मामलों में घोषित मूल्य की अस्वीकृति के लिए यंत्र और प्रक्रिया प्रदान करता है जिनमें युक्तियुक्त संदेह हो कि घोषित मूल्य कारोबार मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है; जहां घोषित मूल्य अस्वीकृत हो जाता है वहां मूल्य का निर्धारण नियम 4 से 9 के अनुसार क्रम से कार्रवाई द्वारा किया जाता है।
- (ii) घोषित मूल्य तब स्वीकृत किया जाता है जब आयातकों के परामर्श से उक्त जांच के बाद उपयुक्त अधिकारी घोषित मूल्य की सत्यता और प्रमाणिकता के बारे में संतुष्ट हो जाते हैं।
- (iii) उपयुक्त अधिकारी को कतिपय कारणों के आधार पर घोषित मूल्य की सत्यता अथवा प्रमाणिकता पर संदेह करने का अधिकार है। इन कतिपय कारणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं -

(क) अत्यधिक मूल्य जिस पर समान अथवा ऐसे ही माल का आयात किया जाता है अथवा उसी समय में तुलनीय वाणिज्यिक कारोबार में तुलनीय मात्राओं में मूल्यांकन किया जाता है;

(ख) विक्रय में बेहिसाब छूट अथवा सामान्य प्रतियोगी मूल्य में बेहिसाब कटौती शामिल हो;

(ग) विक्रय में खास एजेंटों के लिए सीमित विशेष छूट शामिल हो;

(घ) विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, मूल देश, विनिर्माण अथवा उत्पादन वर्ष जैसे पैरामीटरों में माल की गलत घोषणा;

(ङ.) ब्रांड, ग्रेड, विशिष्टीकरण जिनकी मूल्य के साथ प्रासंगिकता है, जैसे पैरामीटरों की घोषणा नहीं करना।

(च) गलत अथवा जाली दस्तावेज

13. **व्याख्यात्मक नोट** - इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्याख्यात्मक नोट इन नियमों की व्याख्या के लिए लागू नहीं होंगे।

अनुसूची
(नियम 13 देखें)
व्याख्यात्मक नोट

सामान्य नोट

सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों का प्रयोग

1. ' सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों का अर्थ है किसी खास समय में देश के अंदर इस बात पर मान्यता प्राप्त सहमति अथवा पर्याप्त प्राधिकरण समर्थन कि किन आर्थिक संसाधनों और जिम्मेदारियों को सम्पत्तियों और देयताओं के रूप में रिकार्ड किया जाए, किस प्रकार सम्पत्तियों और देयताओं तथा उनमें परिवर्तन की माप की जाए, किस सूचना को उजागर किया जाए और किस प्रकार उसे उजागर किया जाए तथा किन वित्तीय विवरणों को तैयार किया जाए। ये मानक सामान्य अनुप्रयोग तथा विस्तृत प्रक्रियाओं और पद्धतियों के विस्तृत दिशा-निर्देश हो सकते हैं।

नियमों पर नोट

नियम 2 पर नोट

नियम 2 (2)(v) में नियमों के उद्देश्यों के लिए एक व्यक्ति का दूसरे पर नियंत्रण समझा जाएगा जब वह व्यक्ति कानूनी अथवा कार्यरूप में दूसरे व्यक्ति के ऊपर दबाव अथवा निर्देश देने की स्थिति में हो।

नियम 3 पर नोट

वास्तव में भुगतान किया गया अथवा देय मूल्य

वास्तव में भुगतान किया गया अथवा देय मूल्य खरीददार द्वारा आयातित माल के लिए विक्रता के लाभार्थ किया गया अथवा किया जाने वाला कुल भुगतान है। भुगतान का अनिवार्य रूप से रकम का अंतरण होना आवश्यक है। भुगतान क्रेडिट पत्रों अथवा परक्राम्य दस्तावेजों द्वारा किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष

भुगतान का उदाहरण क्रेता द्वारा निपटान होगा चाहे वह विक्रेता द्वारा लिये गये ऋण का पूर्ण भाग हो अथवा आंशिक।

उन कार्यकलापों को छोड़कर जिनके लिए नियम 10 में समायोजन का प्रावधान है, क्रेता द्वारा शुरू किये गये कार्यकलापों को विक्रेता को अप्रत्यक्ष भुगतान के रूप में नहीं समझा जाता है, चाहे वह विक्रेता के लिए लाभ के रूप में ही क्यों न हो। इसलिए ऐसे कार्यकलापों की लागतों में आयातित माल के मूल्य के निर्धारण में वास्तव में भुगतान किया गया अथवा देय मूल्य को नहीं जोड़ा जाएगा।

आयातित माल के मूल्य में निम्नलिखित प्रभार अथवा लागतें शामिल नहीं होंगी बशर्ते कि वे आयातित माल के लिए वास्तव में भुगतान किए गए अथवा देय मूल्य से अलग हैं;

(क) औद्योगिक संयंत्र, मशीन अथवा उपस्कर जैसे आयातित माल पर आयात के बाद शुरू किए गए निर्माण करने, बनाने, जोड़ने, रख-रखाव करने अथवा तकनीकी सहायता के लिए प्रभार;

(ख) आयात के बाद परिवहन लागत;

(ग) भारत में शुल्क और कर

वास्तव में भुगतान किया गया अथवा देय मूल्य का अर्थ है आयातित माल के लिए मूल्य/ क्रेता द्वारा विक्रेता को दिये गये डिवीडेंट अथवा अन्य भुगतान जिनका आयातित माल से संबंध नहीं होता है, सीमा शुल्क मूल्य का भाग नहीं होता है।

नियम 3(2) (क) (iii)

ऐसे प्रतिबंध जिनके कारण वास्तव में भुगतान किये गये अथवा देय मूल्य अस्वीकार्य नहीं होते हैं, वे प्रतिबंध हैं, जो माल के मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। ऐसे प्रतिबंधों का एक उदाहरण ऐसा मामला है जहां

विक्रेता ऑटोमोबाइल के क्रेता से निर्धारित तिथि, जो मॉडल वर्ष की शुरुआत का सूचक है, से पूर्व उसे बचने अथवा प्रदर्शित नहीं करने की अपेक्षा करता है।

नियम 3(2)(ख)

यदि विक्रय अथवा मूल्य किसी शर्त अथवा विचार करने के अधीन होता है, जिसके लिए मूल्यांकन किए जा रहे माल के संबंध में मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए कारोबार मूल्य स्वीकार्य नहीं होगा। इसके कुछ उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं;

(क) विक्रेता आयातित माल का मूल्य इस शर्त पर निर्धारित करता है कि क्रेता भी विनिर्दिष्ट मात्राओं में अन्य माल खरीदेगा;

(ख) आयातित माल का मूल्य उस मूल्य अथवा मूल्यों पर निर्भर होता है जिस पर आयातित माल का क्रेता आयातित माल के विक्रेता को अन्य माल बेचता है;

(ग) मूल्य आयातित माल से इतर भुगतान के प्रकार के आधार पर निर्धारित होता है जैसे कि वहां जहां आयातित माल अर्द्धपरिष्कृत माल है जिन्हें विक्रेता द्वारा इस शर्त पर दिया जाता है कि वे विनिर्दिष्ट मात्रा में परिष्कृत माल प्राप्त करेंगे।

तथापि, आयातित माल के उत्पादन अथवा विपणन से संबंधित शर्तें अथवा विचार के परिणामस्वरूप कारोबार मूल्य को अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। उदाहरणार्थ इस तथ्य के परिणामस्वरूप की क्रेता विक्रेता को भारत में शुरू की गई इंजीनियरिंग और योजनाएं प्रदान करता है, नियम 3 के उद्देश्यों के लिए कारोबार मूल्य को अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार यदि क्रेता अपने कारण से विक्रेता के साथ करार के बावजूद आयातित माल के विपणन से संबंधित कार्यकलापों को शुरू करता है, तो इन कार्यकलापों का मूल्य आयातित माल के मूल्य का भाग नहीं होगा और न ही ऐसे कार्यकलापों के कारण कारोबार मूल्य को अस्वीकृत किया जाएगा।

नियम 3(3)

1. नियम 3(3)(क) और नियम 3(3)(ख) कारोबार मूल्य की स्वीकार्यता स्थापित करने के विभिन्न साधन प्रदान करते हैं।

2. नियम 3(3)(क) में यह प्रावधान है कि जहां क्रेता और विक्रेता संबंध होते हैं, विक्रय से संबंधित परिस्थितियों की जांच की जाएगी और कारोबार मूल्य को आयातित माल के मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते कि संबंध से मूल्य प्रभावित नहीं हो। यह अभिप्राय नहीं है कि ऐसे सभी मामलों में परिस्थितियों की जांच हो जहां क्रेता और विक्रेता संबंध हैं। ऐसी जांच तभी अपेक्षित होगी जब मूल्य की स्वीकार्यता के संबंध में संदेह हो। जहां सीमा शुल्क के उपयुक्त अधिकारी को मूल्य की स्वीकार्यता के संबंध में कोई संदेह नहीं हो इसे आयातक से और सूचना मांगे बगैर स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ सीमा शुल्क के उपयुक्त अधिकारी ने संबंध की पहले ही जांच कर ली हो अथवा उन्हें क्रेता और विक्रेता के संबंध में विस्तृत जानकारी पहले से ही हो और वे ऐसी जांच अथवा सूचना से पहले ही संतुष्ट हों कि संबंध से मूल्य प्रभावित नहीं हुआ।
3. जहां सीमा शुल्क का उपयुक्त अधिकारी बिना आगे की पूछताछ के कारोबार मूल्य को स्वीकार करने में असमर्थ हो, वहां उन्हें आयातक को ऐसी विस्तृत सूचना प्रदान करने का अवसर देना चाहिए जिससे विक्रय से संबंधित परिस्थितियों की जांच करने में वे सक्षम हो सकें। इस संदर्भ में सीमा शुल्क के उपयुक्त अधिकारी को जिस तरीके से क्रेता और विक्रेता अपने वाणिज्यिक संबंधों को बनाते हैं और जिस तरीके से सम्बद्ध मूल्य वे निर्धारित करते हैं उस तरीके के साथ-साथ कारोबार के प्रासंगिक पहलुओं की जांच करने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या संबंध से मूल्य प्रभावित हुआ। यदि यह दिखाया जा सकता है कि क्रेता और विक्रेता, हालांकि नियम 2(2) के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित है, एक दूसरे से खरीद सकते हैं और एक दूसरे को बेच सकते हैं यदि वे संबंधित नहीं हों तो इससे यह प्रदर्शित होगा कि मूल्य संबंध से प्रभावित नहीं हुआ है। इसके उदाहरण के तौर पर यदि मूल्य उक्त उद्योग की सामान्य मूल्य प्रक्रियाओं के अनुकूल तरीके से अथवा जिससे विक्रेता ऐसे क्रेता के लिए विक्रय हेतु मूल्य निर्धारित करता है जो संबंधित नहीं है, उस तरीके से मूल्य निर्धारित नहीं होता है तो इससे यह प्रदर्शित होगा कि मूल्य संबंध से प्रभावित नहीं हुआ और उदाहरण के तौर पर जहां यह दर्शाया जाए कि मूल्य सभी प्रकार की लागतों की वसूली

करने और लाभ कमाने को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है जो उसी वर्ग अथवा प्रकार के माल के विक्रय में प्रतिनिधित्व वाली समयावधि (अर्थात् वार्षिक आधार पर) में फर्म द्वारा कमाए गए मुनाफे का प्रतिनिधित्व करता है तो इससे यह प्रदर्शित होगा कि मूल्य प्रभावित नहीं हुआ है।

4. नियम 3(3)(ख) में आयातक के लिए यह दिखाने के लिए अवसर प्रदान करता है कि कारोबार मूल्य सीमा शुल्क के उपयुक्त अधिकारी द्वारा पूर्व में स्वीकृत 'जांच' मूल्य के लगभग करीब है और इसलिए नियम 3 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार्य हैं। जहां नियम 3(3)(ख) के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, वहां नियम 3(3)(क) के अंतर्गत प्रभाव के मुद्दे की जांच अनिवार्य नहीं है। यदि सीमा शुल्क के उपयुक्त अधिकारी के पास संतुष्ट होने के लिए पहले से ही पर्याप्त सूचना हो कि आगे की विस्तृत पूछताछ के बिना नियम 3(3)(ख) में प्रावधान की गई जांचों में से एक की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है उनके लिए आयातक द्वारा यह प्रदर्शित करना अपेक्षित नहीं है कि जांच की जा सकती है। नियम 3(3)(ख) में 'गैर संबंधित क्रेता' शब्दों का अर्थ है ऐसे क्रेता जो विक्रेता से किसी खास मामले में संबंधित नहीं हैं।

नियम 3(3)(ख)

यह निर्धारित करने के लिए कि एक मूल्य दूसरे मूल्य के 'काफी करीब' है अनेक कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन कारकों में आयातित माल की प्रकृति, उद्योग की स्वयं की प्रकृति, मौसम जिसमें माल आयातित की जाती है और क्या मूल्यों में परिवर्तन वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण हैं जैसे कारक शामिल हैं। चूंकि ये कारक मामला दर मामला भिन्न हो सकते हैं, प्रत्येक मामले में निर्धारित प्रतिशतता जैसे एक रूप मानक को लागू करना असंभव होगा। उदाहरणार्थ, यह निर्धारित करने में कि कारोबार मूल्य नियम 3(3)(ख) में दिए गए 'जांच' मूल्यों के काफी करीब है एक प्रकार के माल वाले मामले में मूल्य में थोड़ा अन्तर अस्वीकार्य हो सकता है जबकि दूसरे प्रकार के माल वाले मामले में बड़ा अन्तर स्वीकार्य हो सकता है।

नियम 4 के लिए नोट

1. नियम 4 को लागू करने में सीमा शुल्क का उपयुक्त अधिकारी, जहां भी संभव हो, उसी वाणिज्यिक स्तर पर और लगभग उसी मात्रा में जिसमें माल का मूल्य निर्धारित किया गया है, ऐसे माल का विक्रय कर सकता है। जहां ऐसा कोई विक्रय नहीं होता है, निम्नलिखित तीन शर्तों में से किसी एक के अंतर्गत ऐसे माल का विक्रय किया जा सकता है:

- (क) ऐसे ही वाणिज्यिक स्तर पर परन्तु भिन्न मात्राओं में विक्रय;
- (ख) भिन्न वाणिज्यिक स्तर पर परन्तु उसी मात्रा में विक्रय;
- (ग) भिन्न वाणिज्यिक स्तर पर और भिन्न मात्राओं में विक्रय।

2. इन तीन स्थितियों में से किसी एक के अंतर्गत विक्रय होने पर समायोजन, जैसा मामला हो, निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:

- (क) केवल मात्रा कारकों के लिए;
- (ख) केवल वाणिज्यिक कारकों के लिए; अथवा
- (ग) वाणिज्यिक और मात्रा दोनों कारकों के लिए।

3. नियम 4 के उद्देश्य के लिए ऐसे ही आयातित माल के कारोबार मूल्य का अर्थ है नियम 4(1)(ख) और (ग) तथा नियम 4(2) जिन्हें पहले ही नियम 3 के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया है, में किए गए प्रावधान के अनुसार समायोजित मूल्य।

4. विभिन्न वाणिज्यिक स्तरों अथवा भिन्न मात्राओं के कारण समायोजन के लिए शर्त यह है कि ऐसा समायोजन, चाहे इससे मूल्य में वृद्धि हो अथवा कमी, केवल ऐसे प्रदर्शित साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए जो समायोजन की युक्तियुक्तता तथा प्रमाणिकता अर्थात् भिन्न स्तरों अथवा भिन्न मात्राओं से संबंधित मूल्यों की वैध मूल्य सूचियों को स्पष्टतया प्रदर्शित करता है। इसके उदाहरण के तौर पर यदि मूल्यांकन किए जा रहे आयातित माल में 10 यूनिट लदान हो और एक मात्र ऐसे ही आयातित माल, जिसके लिए कारोबार मूल्य में 500 यूनिट शामिल हो और यह मान लिया जाता है कि विक्रेता मात्रा छूट प्रदान करता है तो अपेक्षित समायोजन विक्रेता की मूल्य सूची तथा 10 यूनिटों के विक्रय के लिए लागू मूल्य के उपयोग द्वारा पूरा किया जा सकता है। इसके लिए यह अपेक्षित नहीं है कि विक्रय 10 की मात्रा में किया गया हो, जहां तक मूल्य

सूची को अन्य मात्राओं में विक्रय के द्वारा उचित ठहराया गया हो। तथापि, ऐसे निष्पक्ष उपाय की अनुपस्थिति में नियम 4 के प्रावधानों के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण उपयुक्त नहीं है।

नियम 5 के लिए नोट

1. नियम 5 को लागू करने में सीमा शुल्क का उपयुक्त अधिकारी, जहां भी संभव हो, ऐसे ही वाणिज्यिक स्तर पर तथा काफी हद तक उसी मात्रा में ऐसे माल का विक्रय करेंगे जिसमें माल का मूल्यांकन किया गया हो। नियम 5 के उद्देश्य के लिए ऐसे ही आयातित माल का कारोबार मूल्य का अर्थ है आयातित माल का मूल्य जिसका समायोजन नियम 3 के अंतर्गत पहले से ही स्वीकृत नियम 5(2) में किए गए प्रावधान के अनुसार किया गया हो।
2. नियम 4 के नोट में अंतर्विष्ट अन्य सभी प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे ही माल के संबंध में लागू होंगे।

नियम 7 के लिए नोट

1. "यूनिट / मूल्य जिस पर माल को सबसे बड़ी मात्रा में बेचा जाता है" का अर्थ है विक्रय में सबसे अधिक संख्या में यूनिटों को ऐसे व्यक्तियों को बेचा जाता है जो उन व्यक्तियों से संबद्ध नहीं हैं जिनसे आयात के बाद प्रथम वाणिज्यिक स्तर पर ऐसे माल खरीदे जाते हैं।
2. उदाहरणार्थ, सामानों की बिक्री एक मूल्य सूची के अनुसार होती है जिससे बड़ी मात्रा में खरीद किए जाने पर अनुकूल इकाई कीमत प्राप्त होती है

बिक्री की मात्रा	इकाई मूल्य	बिक्री संख्या	प्रत्येक मूल्य पर हुई कुल बिक्री मात्रा
1-10 इकाईयां	100	5 इकाइयों की 10 बिक्रियां, 3 इकाइयों की 5 बिक्रियां	65
11-25 इकाईयां	95	11 इकाइयों की 5 बिक्रियां	55

25 इकाईयों से अधिक	90	30 इकाईयों की 1 बिक्री, 50 इकाईयों की 1 बिक्री	80
--------------------	----	---	----

सबसे अधिक मूल्य पर बिक्री इकाईयों की संख्या 80 है अतः सर्वाधिक सकल मात्रा 90 है।

3. इसका दूसरे उदाहरण में दो बिक्रियाँ हुई हैं। पहली बिक्री 500 इकाईयों की हुई है जिसमें प्रत्येक इकाई की कीमत 95 मुद्रा है। दूसरी बिक्री 400 इकाईयों की हुई है जिसमें प्रत्येक इकाई की कीमत 90 मुद्रा है। इस उदाहरण में किसी विशेष मूल्य पर बेची गई इकाईयों की संख्या 500 है अतः सर्वाधिक सकल मात्रा में इकाई मूल्य 95 है।

4. तीसरा उदाहरण निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है जहां विभिन्न मूल्यों पर विभिन्न मात्रा में बिक्री होती है।

(क) बिक्री

बिक्री मात्रा	इकाई मूल्य
40 इकाईयां	100
30 इकाईयां	90
15 इकाईयां	100
50 इकाईयां	95
25 इकाईयां	105
35 इकाईयां	90
5 इकाईयां	100

(ख) योग

बिक्री की कुल मात्रा	इकाई मूल्य
65	90
50	95
60	100
25	105

इस उदाहरण में किसी विशेष मूल्य पर बेची गई इकाईयों की सबसे बड़ी संख्या 65 है अतः सबसे बड़ी निकटतम मात्रा में इकाई मूल्य 90 है।

5. नियम 7 के उद्देश्य से इकाई मूल्य का निर्धारण करने में भारत में होने वाली उस बिक्री पर विचार नहीं किया जाएगा जो, जैसा कि उपर्युक्त पैराग्राफ में वर्णित है, ऐसे व्यक्ति को की गई है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुल कम लागत पर आपूर्ति करता है जो नियम 10(1)(ख) में विनिर्दिष्ट किसी भी तत्व के आयातित माल के निर्यात हेतु उत्पादन और बिक्री से संबंधित है।

6. इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नियम 7(1) में उल्लिखित 'लाभ एवं सामान्य व्यय' की अवधारणा को इसके समग्र अर्थ में लेना चाहिए। इस प्रकार के निगमन के लिए आंकड़ों का निर्धारण आयातकर्ता द्वारा या उसकी ओर से दी गई सूचना के आधार पर तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि उसके द्वारा दिये गये आंकड़े इसी वर्ग या प्रकार के आयातित माल की भारत में बिक्री से प्राप्त आंकड़ों से संगत न साबित होते हों। जहां आयातकर्ता द्वारा दिये गए आंकड़े ऐसे आंकड़ों से मेल नहीं खाते वहां लाभ और साधारण खर्च की राशि का निर्धारण आयातकर्ता द्वारा या उसकी ओर से दिये गये आंकड़ों से भिन्न सुसंगत सूचना के आधार पर किया जा सकता है।

7. 'सामान्य व्यय' में प्रश्नगत माल के विपणन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत को भी शामिल किया गया है।

8. माल की बिक्री के कारण देय स्थानीय कर, जिसके लिए नियम 7(1) (iii) के प्रावधानों के अंतर्गत कोई कटौती नहीं की गई है, के नियम 7(1) (i) के प्रावधानों के अंतर्गत कटौती की जाएगी।

9. नियम 7(1) के प्रावधानों के अंतर्गत कमीशन या सामान्य लाभ और सामान्य व्यय का निर्धारण करने में, यह प्रश्न कि क्या कतिपय माल 'उसी वर्ग या प्रकार' का है जैसा अन्य माल है, निहित परिस्थितियों के मद्देनजर मामले दर मामले के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। एक ही वर्ग या प्रकार के आयातित माल के संकीर्णतम ग्रुप या रेंज की भारत में बिक्री, जिसमें ऐसे माल भी शामिल हैं जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है जिनके बारे में आवश्यक जानकारी दी जा सकती है, की जांच की जानी चाहिए। नियम 7 के प्रयोजन से

"सामान वर्ग या प्रकार के माल" में वे माल आते हैं जो एक ही देश से आयात किये गये हैं जिनका की मूल्यांकन किया गया है और इसमें अन्य देशों से आयात किया गया माल भी शामिल है।

10. नियम 7(2) के प्रयोजन के लिए "निकटतम तारीख" से अभिप्राय उस तारीख से है जिस तारीख तक इकाई मूल्य के निर्धारण के लिए आयातित माल या सदृश्य सामान आयातित माल की पर्याप्त मात्रा में बिक्री की जाती है।

11. जहां नियम 7(3) की विधि का प्रयोग किया गया है, आगे की प्रक्रिया के द्वारा सर्वाधिक मूल्य के लिए की जाने वाली कटौती ऐसे कार्य की लागत से संबंधित लाभ और प्रमाणात्मक आंकड़ों पर की जायेगी। गणनायें स्वीकृत औद्योगिक सूत्रों, रिसाइप्स, निर्माण की विधियों और अन्य औद्योगिक रीतियों पर आधारित होंगी।

12. ऐसी मान्यता है कि नियम 7(3) में दी गई मूल्यांकन की विधियां सामान्यतया तब नहीं लागू होती हैं जब आगे के प्रसंस्करण के परिणामस्वरूप आयातित माल की पहचान समाप्त हो जाती है। हालांकि ऐसे भी उदाहरण हैं जहां, यद्यपि माल की पहचान समाप्त हो जाती है लेकिन बिना किसी गैर वाजिब कठिनाई के प्रसंस्करण के होने वाले मूल्य संवर्धन का सही-सही निर्धारण किया जा सकता है। दूसरी ओर ऐसे भी कुछ उदाहरण हो सकते हैं जहां आयातित माल की तो पहचान बनी रह सकती है लेकिन वे आयात करने वाले देश में बेचे जाने वाले इतने लघु प्रकार के होते हैं कि इनके मूल्यांकन की यह विधि अपनाना न्यायोचित नहीं होता है। अतः उपर्युक्त बातों के मद्देमजर इस प्रकार की प्रत्येक स्थिति में मामले दर मामले के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

नियम 8 पर टिप्पणी

1. एक सामान्य नियम के रूप में आयातित माल के मूल्य का निर्धारण इन नियमों के अंतर्गत तथा भारत में उपलब्ध तात्कालिक सूचना के आधार पर किया जाता है। हालांकि, एक संगणित मूल्य का निर्धारण करने के लिए यह जरूरी होता है कि मूल्यांकन किए जाने वाले माल की उत्पादन लागत की तथा अन्य सूचनाओं की, जो भारत के बाहर से प्राप्त होती है, जांच-परख की जानी चाहिए। इसके अलावा, अधिकांश मामलों में माल

के उत्पादक मुख्य अधिकारियों के क्षेत्राधिकार के बाहर होंगे। संगणित मूल्य के प्रयोग की विधि सामान्त्या उन्हीं मामलों तक सीमित होगी जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों ही संबंधित हैं और उत्पादक मुख्य अधिकारी को जरूरी लागत देने के लिए और यदि जरूरी हुआ तो बाद में होने वाले सत्यापन के लिए अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार हैं।

2. नियम 8 के उप वाक्य(क) में वर्णित "लागत या मूल्य" का निर्धारण इन सूचनाओं के आधार पर किया जाना है जो मूल्यांकित किए जाने वाले माल, जिनकी आपूर्ति उत्पादक के द्वारा या उसकी ओर से की गई है, से संबंधित हैं। यह उत्पादक के वाणिज्यिक खाते पर आधारित होनी चाहिए बशर्ते कि यह खाता उस देश में प्रचलित लेखा प्रणाली से सामांजस्य रखता हो जहां कि ऐसे माल का उत्पादन हुआ है।
3. "लागत और मूल्य" उन अवयवों की लागत शामिल है जो नियम 10 के उपवाक्य 1 (क) (II) और (1)(क) (III) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। इसमें उन अवयवों का मूल्य भी शामिल है जो नियम 10(1)(ख) में विनिर्दिष्ट है तथा आयातित माल के उत्पादन के संबंध में प्रयोग के लिए क्रेता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपूर्ति किए गए हैं, जिन्हें नियम 10 के प्रावधानों के अंतर्गत एक हिस्सा माना गया है। नियम 10(1) (ख)(4) में विनिर्दिष्ट अवयवों का मूल्य, जिसका निर्धारण भारत में किया जाता है, उसी सीमा तक लिया जाएगा जिस सीमा तक ऐसा अवयवों उत्पादक पर भारित किया जाता है। यह भी समझने की जरूरत है कि इस पैराग्राफ में वर्णित अवयवों का कोई मूल्य या लागत को संगणित मूल्य के निर्धारण में दोबारा शामिल नहीं किया जाएगा।
4. नियम 8 के उपवाक्य "ख" में वर्णित "लाभ और सामान्य व्यय" की राशि का निर्धारण तब तक उत्पादक या उसकी ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर किया जाएगा जब तक कि उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े उन आंकड़ों से बेमेल नहीं होते हैं जो कि उसी वर्ग या प्रकार के माल की सामान्य बिक्री से जाहिर होते हैं जोकि उत्पादक द्वारा भारत में निर्यात किए जाने के लिए विनिर्मित किए गए हैं।
5. इस संदर्भ में इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि "लाभ और सामान्य व्यय" को हमको उसके समग्र रूप में देखना चाहिए। इसका तात्पर्य यह होता है कि किसी विशेष मामले में यदि उत्पादकों का लाभ कम है और उसका खर्चा अधिक है तो उत्पादक का लाभ और सामान्य व्यय दोनों मिलकर उस मूल्य से सामांजस्य रख सकते हैं जो उसी वर्ग

या प्रकार के माल की बिक्री से साधारणतया प्रकट होता है। ऐसी स्थिति आ सकती है कि, उदाहरणस्वरूप, यदि उत्पाद को भारत में भेजा जा रहा है और उत्पादक को लाभ शून्य के बराबर है या बहुत कम मिल रहा है तो ऐसे उत्पाद को बाजार में लाने पर सामान्य व्यय कम हो जाएगा। जहां किसी विशेष वाणिज्यिक परिस्थिति के कारण अपने आयातित माल की बिक्री में उत्पादक कम लाभ प्रदर्शित करता है, तो उसके वास्तविक लाभ पर ही विचार किया जाना चाहिए बशर्ते कि उसके पास इसे सिद्ध करने का वैध वाणिज्यिक कारण होना चाहिए और उसकी मूल्य नीति में संबंधित औद्योगिक शाखा की साधारण मूल्य नीति परिलक्षित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, जहां कि उत्पादक को स्थाई तौर पर कम कीमत स्वीकार करनी पड़ सकती है क्योंकि मांग में अप्रत्याशित कमी आ सकती है या वे भारत में उत्पादित माल के पूरक के रूप में अपना माल बेचते हैं और प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए कम कीमत स्वीकार करते हैं। जहां की लाभ और सामान्य खर्च के बारे में उत्पादक के अपने आंकड़े मूल्य निर्धारित किए जाने वाले माल के वर्ग या प्रकार वाले दूसरे ऐसे माल की सामान्य बिक्री से होने वाले लाभ और खर्च से मेल नहीं खाते हैं जोकि निर्यात करने वाले देश के उत्पादक द्वारा भारत में निर्यात करने के लिए विनिर्मित किए गए हैं, वहां लाभ और सामान्य खर्च की राशि का निर्धारण माल के उत्पादक के द्वारा या उसकी ओर से दी गई सूचनाओं से भिन्न अन्य सुसंगत सूचनाओं के आधार पर किया जाएगा।

6. नियम 8 के उपवाक्य "ख" में उल्लिखित "सामान्य लाभ" में निर्यात के माल के उत्पादन और बिक्री पर आने वाले वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत शामिल हैं जो कि नियम 8 के उपवाक्य (क) में शामिल नहीं हैं।
7. क्या कोई माल अन्य माल के "वर्ग या प्रकार" का है इस बात का निर्धारण मामले दर मामले के आधार पर तथा इसमें विद्यमान परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। नियम 8 के प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य लाभ और साधारण खर्च का निर्धारण करने में संकीर्णतम समूह या रेंज के माल की भारत में निर्यात किए जाने के लिए हो रही बिक्री, इसमें वह माल भी शामिल है जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है और जिसके बारे में आवश्यक जानकारी दी जा सके, पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नियम 8 के प्रयोजन के लिए "किसी वर्ग या प्रकार का माल"

उसी देश का होना चाहिए जिस देश का वह माल है जिसका कि मूल्यांकन किया जाना है।

नियम 9 पर टिप्पणी

1. नियम 9 के प्रावधानों के अंतर्गत आयातित माल के मूल्य का निर्धारण, यथासंभव, इसके पहले निर्धारित सीमा शुल्क मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए।

2. नियम 9 के प्रावधानों के अंतर्गत मूल्यांकन की वही विधि अपनाई जानी चाहिए जो नियम 3 से 8 में दी गई है लेकिन इसमें नियम 9 के उद्देश्य और प्रावधानों के अनुकूल युक्तियुक्त लचीलापन भी होना चाहिए।

3. युक्तियुक्त लचीलेपन के कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं :-

(क) सदृश्य माल - इस आवश्यकता कि जिस समय माल का मूल्यांकन किया जा रहा है या उस समय के आसपास सदृश्य माल का आयात किया जाना चाहिए, की व्याख्या में लचीलापन अपनाया जा सकता है; मूल्यांकन किये जा रहे माल का निर्यात करने वाले देश के अलावा अन्य किसी देश में विनिर्मित आयातित सदृश्य माल को सीमा शुल्क के मूल्यांकन का आधार बनाया जा सकता है, नियम 7 और 8 के प्रावधानों के अंतर्गत सदृश्य आयातित माल के निर्धारित सीमा शुल्क का ही प्रयोग किया जा सकता है।

(ख) समान माल - इस आवश्यकता कि जिस समय माल का मूल्यांकन किया जा रहा है या उस समय के आसपास समान माल का आयात किया जाना चाहिए, की व्याख्या में लचीलापन अपनाया जा सकता है। मूल्यांकन किए जा रहे माल का निर्यात करने वाले देश के अलावा अन्य देश में विनिर्मित आयातित समान माल को सीमाशुल्क के मूल्यांकन का आधार बनाया जा सकता है; नियम 7 और 8 के प्रावधानों के अंतर्गत समान प्रकार के आयातित माल का पहले निर्धारित किए गए सीमा शुल्क मूल्य का प्रयोग किया जा सकता है।

(ग) निगमनात्मक विधि - इस आवश्यकता, कि जिन परिस्थितियों के अंतर्गत नियम 7(1) में आयात किया गया है उन्हीं परिस्थितियों में माल को बेच दिया

गया होगा " की व्याख्या लचीलेपन ढंग से की जानी चाहिए; 90 दिन की आवश्यकता को लचीलेपन के साथ लागू करना चाहिए।

नियम 10 पर टिप्पणी

नियम 10(1)क(i) में " क्रय आदत " से तात्पर्य ऐसे शुल्क से है जो आयातकर्ता अपने अभिकर्ता को उस सेवा के बदले देता है जिसके अंतर्गत अभिकर्ता ने मूल्यांकन संबंधी माल की खरीद में आयातकर्ता का देश के बाहर प्रतिनिधित्व किया है।

1. नियम 10(1)(ख) (ii) के अनुसार आयातित माल के तत्व के प्रमाणन में दो कारक निहित हैं - पहला स्वयं तत्व का मूल्य और दूसरा वह तरीका जिससे आयातित माल का मूल्य प्रभाजन किया जाता है। इन तत्वों का प्रभाजन ऐसे युक्तियुक्त तरीके से किया जाना चाहिए जो परिस्थितियों की दृष्टि से यथोचित हों और सामान्यतया स्वीकृत लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुकूल हों।

2. जहां तक तत्व के मूल्य का संबंध है यदि आयातकर्ता किसी ऐसे क्रेता से, जो उससे संबंधित नहीं है, दिये गये मूल्य पर इन तत्वों को खरीदता है तो यह लागत इस तत्व का मूल्य होगी। यदि तत्व का उत्पादन आयातकर्ता द्वारा या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है तो इसका मूल्य वही हो जो इसके उत्पादन पर आने वाली लागत है। यदि तत्व का उपयोग आयातकर्ता द्वारा पहले किया जा चुका है तो चाहे ऐसे आयातकर्ता द्वारा यह उत्पादित किया गया हो या खरीदा गया हो, उसकी खरीद या उत्पादन की मूल लागत को समायोजित करके घटा दिया जाना चाहिए जिससे की यह पता लगे कि इसका उपयोग किया गया है और तदनुसार मूल्य निर्धारण किया जाए।

3. एक बार यदि तत्व का मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है तो आयातित माल में इस मूल्य का प्रभाजन आवश्यक है। इसके लिए कई संभावनाएं विद्यमान हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आयातकर्ता एक ही बार में सारा शुल्क अदा करना चाहता है तो पहली खेप में ही मूल्य का प्रभाजन किया जा सकता है। दूसरा उदाहरण यह हो सकता है कि आयातकर्ता यह अनुरोध कर सकता है कि पहली खेप के समय उत्पादित इकाईयों पर मूल्य प्रभाजन किया जाए। एक और उदाहरण के तौर पर, वह यह अनुरोध कर सकता है कि जहां उत्पादन के लिए

अनुबंध या फर्म की वचनबद्धता निहित है वहां संपूर्ण प्रत्याशित उत्पादन पर मूल्य प्रभाजन किया जाए। प्रयोग में लाए जाने वाले प्रभाजन की विधि आयातकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों पर निर्भर करेगी।

4. उपर्युक्त के दृष्टांत के रूप में कोई आयातकर्ता उत्पादक को सांचा प्रदान करता है जिसका उत्पादन में प्रयोग किया जाना है और उससे 10 हजार इकाईयां खरीदने का अनुबंध करता है। 10000 इकाईयों की पहली खेप के पहुंचने पर उत्पादक ने पहले ही 4000 इकाईयों का उत्पादन कर लिया है। ऐसी स्थिति में आयातकर्ता सीमा शुल्क के उचित अधिकांश से 1000 इकाईयों पर 4000 इकाईयों पर या 10 हजार इकाईयों पर सांचे के मूल्य का प्रभाजन करने के लिए अनुरोध कर सकता है।

नियम 10(1)(ख) (iv)

1. नियम नियम 10(1)(ख) (iv) में तत्वों में कोई बढ़ोतरी उद्देश्य और प्रमाणात्मक आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। संवर्द्धित किए जाने वाले मूल्य के निर्धारण में यथोचित अधिकारी और आयातकर्ता दोनों के ही भार को कम करने के लिए क्रेता के वाणिज्यिक रिकार्ड प्रणाली में उपलब्ध तैयार आंकड़ों का यथासंभव प्रयोग किया जा सकता है।

2. उन तत्व के मामले में जो क्रेता द्वारा आपूर्ति किए गए हैं, जिनको क्रेता द्वारा खरीदा या या पट्टे पर लिया गया है, इसके खरीद पर पट्टे की लागत के बराबर ही संवर्द्धन किया जा सकता है। जन सामान्य के अधिकार में रहने वाले तत्वों के मामले में सिवाय उसकी प्रतियां तैयार करने में आने वाली लागत के कोई मूल्यवर्द्धन नहीं होगा।

3. ऐसे मामलों में जिनमें गणना करना संभव है संवर्द्धित किये जाने वाला मूल्य फर्म विशेष की संरचना और प्रबंधन के तरीके तथा साथ ही साथ इसकी लेखा पद्धति पर निर्भर करेंगे।

4. उदाहरण के लिए, ऐसा संभव है कि कोई फर्म जो विभिन्न देशों से कई किस्मों का आयात कर रही हो, आयात संबंधी देश के बाहर अपनी डिजाइन सेंटर के बारे में ऐसे दस्तावेज रखती हो जिससे उत्पाद की लागत का पता

शुद्धतापूर्वक लग सकता है। ऐसे मामलों में नियम 10 के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित रूप से सीधा समायोजन किया जा सकता है।

5. अन्य मामले में कोई फर्म आयात संबंधी देश के बाहर अपनी डिजाइन सेंटर की लागत को बिना किसी उत्पाद को आबंटित किये सामान्य उपरी शीर्ष व्यय के रूप में दिखा सकती है। इस उदाहरण में कुल उत्पादन पर कुल डिजाइन सेंटर लागत का प्रयोजन करके नियम 10 के प्रावधानों के अंतर्गत आयातित माल के संबंध में यथोचित समायोजन कर किया जा सकता है और इससे डिजाइन सेंटर से लाभ होगा और आयात के उद्देश्य से इकाई आधार पर प्रयोजन लागत को जोड़ा जा सकता है।

6. निसंदेह रूप से उपर्युक्त परिस्थितियों में भिन्नता होने से, आबंटन के लिए संबंधित निधि के निर्धारण में विभिन्न कारणों पर विचार किया जाना जरूरी है।

7. ऐसे मामलों जहां प्रश्नगत तत्वों के उत्पादन में कई देश शामिल हैं और इसमें भिन्न-2 समय लग रहा है तो समायोजन आयात संबंधी देश के बाहर तत्वों में वास्तविक रूप से वर्धित किए गए मूल्य तक सीमित होगा।

नियम 10(1)(ग)

1. नियम 10(1)(ग) में उल्लिखित रायल्टी और लाइसेंस शुल्कों में अन्य बातों के साथ-2 पेटेंट ट्रेडमार्क और कापीराइट संबंधी भुगतान भी शामिल है। हालांकि आयात संबंधी देश में आयातित माल के पुनरोत्पादन के अधिकार पर लगने वाले प्रभार को उस मूल्य में नहीं जोड़ा जाएगा। जिसका वास्तविक रूप से भुगतान किया गया है या सीमा शुल्क के मूल्य के निर्धारण में आयातित माल के लिए भुगतान योग्य है।

2. आयातित माल के वितरण या पुनः बिक्री के अधिकार के लिए क्रेता द्वारा किए गए भुगतान को उस मूल्य के साथ नहीं जोड़ा जाएगा जो आयातित माल के लिए वास्तव में भुगतान किया गया है या जिसका भुगतान किया जाना है। यदि ऐसे भुगतान को माल को आयात करने वाले देश को की जाने वाली बिक्री के लिए शर्त नहीं माना गया है।

नियम 10(3)

जहां नियम 10 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक संवर्धन के लिए कोई वस्तुनिष्ठ या मात्रात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो नियम 3 के प्रावधानों के अंतर्गत संव्यवहार के मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसके एक दृष्टांत के रूप में रॉयल्टी का भुगतान किसी विशेष उत्पाद का आयातकर्ता देश में होने वाली एक लीटर के बिक्री के मूल्य के आधार पर किया जाता है, यदि इसका आयात किलोग्राम के हिसाब से किया गया है और इसका विलयन तैयार किया गया है। यदि रॉयल्टी अंशतः आयातित माल और अंशतः अन्य कारकों पर आधारित है तो, जहां ऐसे कारकों पर आयातित माल से कोई लेना देना नहीं है, (जैसे कि जब आयातित माल को घरेलू अवयव में मिला दिया जाता है और फिर इनको अलग नहीं किया जा सकता है या रायल्टी को क्रेता या विक्रेता के बीच हुए विशेष व्यवस्थाओं के कारण अलग नहीं किया जा सकता है) तो रॉयल्टी में वृद्धि किए जाने का कोई भी प्रयास यथोचित नहीं होगा। हालांकि, यदि इस रायल्टी की राशि आयातित माल पर आधारित है और इसकी प्रमात्रा का तुरंत निर्धारण हो सकता है तो वास्तविक रूप से किये गये भुगतान या देय भुगतान में वृद्धि की जा सकती है।

[फा. सं. 467/35/2007-सीमा शुल्क-5]

असीम कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2007

No. 94/2007-Customs (N. T.)

G.S.R. 592(E).—In exercise of the powers conferred by Section 156 read with Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the Customs Valuation (Determination of

Price of Imported Goods) Rules, 1988 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Customs Valuation (Determination of Value of Imported Goods) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the 10th day of October, 2007.

(3) They shall apply to imported goods.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "computed value" means the value of imported goods determined in accordance with rule 8.

(b) "deductive value" means the value determined in accordance with rule 7.

(c) "goods of the same class or kind", means imported goods that are within a group or range of imported goods produced by a particular industry or industrial sector and includes identical goods or similar goods;

(d) "identical goods" means imported goods -

(i) which are same in all respects, including physical characteristics, quality and reputation as the goods being valued except for minor differences in appearance that do not affect the value of the goods;

(ii) produced in the country in which the goods being valued were produced; and

(iii) produced by the same person who produced the goods, or where no such goods are available, goods produced by a different person,

but shall not include imported goods where engineering, development work, art work, design work, plan or sketch undertaken in India were completed directly or indirectly by the buyer on these imported goods free of charge or at a reduced cost for use in connection with the production and sale for export of these imported goods;

(e) "produced" includes grown, manufactured and mined

(f) "similar goods" means imported goods -

(i) which although not alike in all respects, have like characteristics and like component materials which enable them to perform the same functions and to be commercially interchangeable with the goods being valued having regard to the quality, reputation and the existence of trade mark;

(ii) produced in the country in which the goods being valued were produced; and

(iii) produced by the same person who produced the goods being valued, or where no such goods are available, goods produced by a different person,

but shall not include imported goods where engineering, development work, art work, design work, plan or sketch undertaken in India were completed directly or indirectly by the buyer on these imported goods free of charge or at a reduced cost for use in connection with the production and sale for export of these imported goods;

(g) "transaction value" means the value referred to in sub-section (1) of section 14 of the Customs Act, 1962;

(2) For the purpose of these rules, persons shall be deemed to be "related" only if -

- (i) they are officers or directors of one another's businesses;
- (ii) they are legally recognised partners in business;
- (iii) they are employer and employee;
- (iv) any person directly or indirectly owns, controls or holds five per cent or more of the outstanding voting stock or shares of both of them;
- (v) one of them directly or indirectly controls the other;
- (vi) both of them are directly or indirectly controlled by a third person;

379562/07-5

- (vii) together they directly or indirectly control a third person; or
- (viii) they are members of the same family.

Explanation I. - The term "person" also includes legal persons.

Explanation II. - Persons who are associated in the business of one another in that one is the sole agent or sole distributor or sole concessionaire, howsoever described, of the other shall be deemed to be related for the purpose of these rules, if they fall within the criteria of this sub-rule.

3. Determination of the method of valuation.- (1) Subject to rule 12, the value of imported goods shall be the transaction value adjusted in accordance with provisions of rule 10;

(2) Value of imported goods under sub-rule (1) shall be accepted:

Provided that -

(a) there are no restrictions as to the disposition or use of the goods by the buyer other than restrictions which -

(i) are imposed or required by law or by the public authorities in India; or

(ii) limit the geographical area in which the goods may be resold; or

(iii) do not substantially affect the value of the goods;

(b) the sale or price is not subject to some condition or consideration for which a value cannot be determined in respect of the goods being valued;

(c) no part of the proceeds of any subsequent resale, disposal or use of the goods by the buyer will accrue directly or indirectly to the seller, unless an appropriate adjustment can be made in accordance with the provisions of rule 10 of these rules; and

(d) the buyer and seller are not related, or where the buyer and seller are related, that transaction value is acceptable for customs purposes under the provisions of sub-rule (3) below.

(3) (a) Where the buyer and seller are related, the transaction value shall be accepted provided that the examination of the circumstances of the sale of the imported goods indicate that the relationship did not influence the price.

(b) In a sale between related persons, the transaction value shall be accepted, whenever the importer demonstrates that the declared value of the goods being valued, closely approximates to one of the following values ascertained at or about the same time.

- (i) the transaction value of identical goods, or of similar goods, in sales to unrelated buyers in India;
- (ii) the deductive value for identical goods or similar goods;
- (iii) the computed value for identical goods or similar goods;

Provided that in applying the values used for comparison, due account shall be taken of demonstrated difference in commercial levels, quantity levels, adjustments in accordance with the provisions of rule 10 and cost incurred by the seller in sales in which he and the buyer are not related;

(c) substitute values shall not be established under the provisions of clause (b) of this sub-rule.

(4) if the value cannot be determined under the provisions of sub-rule (1), the value shall be determined by proceeding sequentially through rule 4 to 9.

4. Transaction value of identical goods. — (1)(a) Subject to the provisions of rule 3, the value of imported goods shall be the transaction value of identical goods sold for export to India and imported at or about the same time as the goods being valued;

Provided that such transaction value shall not be the value of the goods provisionally assessed under section 18 of the Customs Act, 1962.

- (b) In applying this rule, the transaction value of identical goods in a sale at the same commercial level and in substantially the same quantity as the goods being valued shall be used to determine the value of imported goods.
- (c) Where no sale referred to in clause (b) of sub-rule (1), is found, the transaction value of identical goods sold at a different commercial level or in different quantities or both, adjusted to take account of the difference attributable to commercial level or to the quantity or both, shall be used, provided that such adjustments shall be made on the basis of demonstrated evidence which clearly establishes the reasonableness and accuracy of the adjustments, whether such adjustment leads to an increase or decrease in the value.

(2) Where the costs and charges referred to in sub-rule (2) of rule 10 of these rules are included in the transaction value of identical goods, an adjustment shall be made, if there are significant differences in such costs and charges between the goods being valued and

the identical goods in question arising from differences in distances and means of transport.

(3) In applying this rule, if more than one transaction value of identical goods is found, the lowest such value shall be used to determine the value of imported goods.

5. Transaction value of similar goods. — (1) Subject to the provisions of rule 3, the value of imported goods shall be the transaction value of similar goods sold for export to India and imported at or about the same time as the goods being valued:

Provided that such transaction value shall not be the value of the goods provisionally assessed under section 18 of the Customs Act, 1962.

(2) The provisions of clauses (b) and (c) of sub-rule (1), sub-rule (2) and sub-rule (3), of rule 4 shall, *mutatis mutandis*, also apply in respect of similar goods.

6. Determination of value where value can not be determined under rules 3, 4 and 5. — If the value of imported goods cannot be determined under the provisions of rules 3, 4 and 5, the value shall be determined under the provisions of rule 7 or, when the value cannot be determined under that rule, under rule 8.

Provided that at the request of the importer, and with the approval of the proper officer, the order of application of rules 7 and 8 shall be reversed.

7. Deductive value. — (1) Subject to the provisions of rule 3, if the goods being valued or identical or similar imported goods are sold in India, in the condition as imported at or about the time at which the declaration for determination of value is presented, the value of imported goods shall be based on the unit price at which the imported goods or identical or similar imported goods are sold in the greatest aggregate quantity to persons who are not related to the sellers in India, subject to the following deductions : —

(i) either the commission usually paid or agreed to be paid or the additions usually made for profits and general expenses in connection with sales in India of imported goods of the same class or kind;

(ii) the usual costs of transport and insurance and associated costs incurred within India;

(iii) the customs duties and other taxes payable in India by reason of importation or sale of the goods.

(2) If neither the imported goods nor identical nor similar imported goods are sold at or about the same time of importation of the goods being valued, the value of imported goods shall, subject otherwise to the provisions of sub-rule (1), be based on the unit price at which the imported goods or identical or similar imported goods are sold in India, at the earliest date after importation but before the expiry of ninety days after such importation.

- (3) (a) If neither the imported goods nor identical nor similar imported goods are sold in India in the condition as imported, then, the value shall be based on the unit price at which the imported goods, after further processing, are sold in the greatest aggregate quantity to persons who are not related to the seller in India.

(b) In such determination, due allowance shall be made for the value added by processing and the deductions provided for in items (i) to (iii) of sub-rule (1).

8. Computed value. — Subject to the provisions of rule 3, the value of imported goods shall be based on a computed value, which shall consist of the sum of:-

(a) the cost or value of materials and fabrication or other processing employed in producing the imported goods;

(b) an amount for profit and general expenses equal to that usually reflected in sales of goods of the same class or kind as the goods being valued which are made by producers in the country of exportation for export to India;

(c) the cost or value of all other expenses under sub-rule (2) of rule 10.

9. Residual method. — (1) Subject to the provisions of rule 3, where the value of imported goods cannot be determined under the provisions of any of the preceding rules, the value shall be determined using reasonable means consistent with the principles and general provisions of these rules and on the basis of data available in India;

Provided that the value so determined shall not exceed the price at which such or like goods are ordinarily sold or offered for sale for delivery at the time and place of importation in the course of international trade, when the seller or buyer has no interest in the business of other and price is the sole consideration for the sale or offer for sale.

(2) No value shall be determined under the provisions of this rule on the basis of —

- (i) the selling price in India of the goods produced in India;
- (ii) a system which provides for the acceptance for customs purposes of the highest of the two alternative values;
- (iii) the price of the goods on the domestic market of the country of exportation;
- (iv) the cost of production other than computed values which have been determined for identical or similar goods in accordance with the provisions of rule 8;
- (v) the price of the goods for the export to a country other than India;
- (vi) minimum customs values; or

(vii) arbitrary or fictitious values.

10. Cost and services. -(1) In determining the transaction value, there shall be added to the price actually paid or payable for the imported goods, —

- (a) the following to the extent they are incurred by the buyer but are not included in the price actually paid or payable for the imported goods, namely:-
 - (i) commissions and brokerage, except buying commissions;
 - (ii) the cost of containers which are treated as being one for customs purposes with the goods in question;
 - (iii) the cost of packing whether for labour or materials;
- (b) The value, apportioned as appropriate, of the following goods and services where supplied directly or indirectly by the buyer free of charge or at reduced cost for use in connection with the production and sale for export of imported goods, to the extent that such value has not been included in the price actually paid or payable, namely:-
 - (i) materials, components, parts and similar items incorporated in the imported goods;
 - (ii) tools, dies, moulds and similar items used in the production of the Imported goods;
 - (iii) materials consumed in the production of the imported goods;
 - (iv) engineering, development, art work, design work, and plans and sketches undertaken elsewhere than in India and necessary for the production of the imported goods;
- (c) royalties and licence fees related to the imported goods that the buyer is required to pay, directly or indirectly, as a condition of the sale of the goods being valued, to the extent that such royalties and fees are not included in the price actually paid or payable;
- (d) The value of any part of the proceeds of any subsequent resale, disposal or use of the imported goods that accrues, directly or indirectly, to the seller;
- (e) all other payments actually made or to be made as a condition of sale of the imported goods, by the buyer to the seller, or by the buyer to a third party to satisfy an obligation of the seller to the extent that such payments are not included in the price actually paid or payable.

Explanation.- Where the royalty, licence fee or any other payment for a process, whether patented or otherwise, is includible referred to in clauses (c) and (e), such charges shall

be added to the price actually paid or payable for the imported goods, notwithstanding the fact that such goods may be subjected to the said process after importation of such goods.

(2) For the purposes of sub-section (1) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and these rules, the value of the imported goods shall be the value of such goods, for delivery at the time and place of importation and shall include —

- (a) the cost of transport of the imported goods to the place of importation;
- (b) loading, unloading and handling charges associated with the delivery of the imported goods at the place of importation; and
- (c) the cost of insurance :

Provided that —

- (i) where the cost of transport referred to in clause (a) is not ascertainable, such cost shall be twenty per cent of the free on board value of the goods;
- (ii) the charges referred to in clause (b) shall be one per cent of the free on board value of the goods plus the cost of transport referred to in clause (a) plus the cost of insurance referred to in clause (c);
- (iii) where the cost referred to in clause (c) is not ascertainable, such cost shall be 1.125% of free on board value of the goods;

Provided further that in the case of goods imported by air, where the cost referred to in clause (a) is ascertainable, such cost shall not exceed twenty per cent of free on board value of the goods:

Provided also that where the free on board value of the goods is not ascertainable, the costs referred to in clause (a) shall be twenty per cent of the free on board value of the goods plus cost of insurance for clause (i) above and the cost referred to in clause (c) shall be 1.125% of the free on board value of the goods plus cost of transport for clause (iii).

Provided also that in case of goods imported by sea stuffed in a container for clearance at an Inland Container Depot or Container Freight Station, the cost of freight incurred in the movement of container from the port of entry to the Inland Container Depot or Container Freight Station shall not be included in the cost of transport referred to in clause (a).

Explanation.- The cost of transport of the imported goods referred to in clause (a) includes the ship demurrage charges on chartered vessels, lighterage or barge charges.

- (3) Additions to the price actually paid or payable shall be made under this rule on the basis of objective and quantifiable data.
- (4) No addition shall be made to the price actually paid or payable in determining the value of the imported goods except as provided for in this rule.

11. Declaration by the importer. — (1) The importer or his agent shall furnish -

- (a) a declaration disclosing full and accurate details relating to the value of imported goods; and
 - (b) any other statement, information or document including an invoice of the manufacturer or producer of the imported goods where the goods are imported from or through a person other than the manufacturer or producer, as considered necessary by the proper officer for determination of the value of imported goods under these rules.
- (2) Nothing contained in these rules shall be construed as restricting or calling into question the right of the proper officer of customs to satisfy himself as to the truth or accuracy of any statement, information, document or declaration presented for valuation purposes.
- (3) The provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) relating to confiscation, penalty and prosecution shall apply to cases where wrong declaration, information, statement or documents are furnished under these rules.

12. Rejection of declared value. — (1) When the proper officer has reason to doubt the truth or accuracy of the value declared in relation to any imported goods, he may ask the importer of such goods to furnish further information including documents or other evidence and if, after receiving such further information, or in the absence of a response of such importer, the proper officer still has reasonable doubt about the truth or accuracy of the value so declared, it shall be deemed that the transaction value of such imported goods cannot be determined under the provisions of sub-rule (1) of rule 3.

(2) At the request of an importer, the proper officer, shall intimate the importer in writing the grounds for doubting the truth or accuracy of the value declared in relation to goods imported by such importer and provide a reasonable opportunity of being heard, before taking a final decision under sub-rule (1).

Explanation.—(1) For the removal of doubts, it is hereby declared that:—

(i) This rule by itself does not provide a method for determination of value, it provides a mechanism and procedure for rejection of declared value in cases where there is reasonable doubt that the declared value does not represent the transaction value; where the declared value is rejected, the value shall be determined by proceeding sequentially in accordance with rules 4 to 9.

(ii) The declared value shall be accepted where the proper officer is satisfied about the truth and accuracy of the declared value after the said enquiry in consultation with the importers.

(iii) The proper officer shall have the powers to raise doubts on the truth or accuracy of the declared value based on certain reasons which may include -

- (a) the significantly higher value at which identical or similar goods imported at or about the same time in comparable quantities in a comparable commercial transaction were assessed;
- (b) the sale involves an abnormal discount or abnormal reduction from the ordinary competitive price;
- (c) the sale involves special discounts limited to exclusive agents;
- (d) the misdeclaration of goods in parameters such as description, quality, quantity, country of origin, year of manufacture or production;
- (e) the non declaration of parameters such as brand, grade, specifications that have relevance to value;
- (f) the fraudulent or manipulated documents.

13. Interpretative notes. — The interpretative notes specified in the Schedule to these rules shall apply for the interpretation of these rules.

The Schedule
(See rule 13)
Interpretative Notes

General Note:

Use of generally accepted accounting principles

1. "Generally accepted accounting principles" refers to the recognized consensus or substantial authoritative support within a country at a particular time as to which economic resources and obligations shall be recorded as assets and liabilities, which changes in assets and liabilities should be recorded, how the assets and liabilities and changes in them should be measured, what information should be disclosed and how it should be disclosed and which financial statements should be prepared. These standards may be broad guidelines of general application as well as detailed practices and procedures.

Notes to rules**Note to rule 2**

In rule 2(2)(v), for the purposes of these rules, one person shall be deemed to control another when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter.

Note to rule 3**Price actually paid or payable**

The price actually paid or payable is the *total payment* made or to be made by the buyer to or for the benefit of the seller for the imported goods. The payment need not necessarily take the form of a transfer of money. Payment may be made by way of letters of credit or negotiable instruments. *Payment may be made directly or indirectly.* An example of an indirect payment would be the settlement by the buyer, whether in whole or in part, of a debt owed by the seller.

Activities undertaken by the buyer on his own account, other than those for which an adjustment is provided in rule 10, are not considered to be an indirect payment to the seller, even though they might be regarded as of benefit to the seller. The costs of such activities shall not, therefore, be added to the price actually paid or payable in determining the value of imported goods.

The value of imported goods shall not include the following charges or costs, provided that they are distinguished from the price actually paid or payable for the imported goods:

- (a) Charges for construction, erection, assembly, maintenance or technical assistance, undertaken after importation on imported goods such as industrial plant, machinery or equipment;
- (b) The cost of transport after importation;
- (c) Duties and taxes in India.

The price actually paid or payable refers to the price for the imported goods. Thus the flow of dividends or other payments from the buyer to the seller that do not relate to the imported goods are not part of the customs value.

Rule 3(2)(a) (iii)

Among restrictions which would not render a price actually paid or payable unacceptable are restrictions which do not substantially affect the value of the goods. An example of such restrictions would be the case where a seller requires a buyer of automobiles not to sell or exhibit them prior to a fixed date which represents the beginning of a model year.

Rule 3(2)(b)

If the sale or price is subject to some condition or consideration for which a value cannot be determined with respect to the goods being valued, the transaction value shall not be acceptable for customs purposes. Some examples of this include-

(a) The seller establishes the price of the imported goods on condition that the buyer will also buy other goods in specified quantities;

(b) the price of the imported goods is dependent upon the price or prices at which the buyer of the imported goods sells other goods to the seller of the imported goods;

(c) the price is established on the basis of a form of payment extraneous to the imported goods, such as where the imported goods are semifinished goods which have been provided by the seller on condition that he will receive a specified quantity of the finished goods.

However, conditions or considerations relating to the production or marketing of the imported goods shall not result in rejection of the transaction value. For example, the fact that the buyer furnishes the seller with engineering and plans undertaken in India shall not result in rejection of the transaction value for the purposes of rule 3. Likewise, if the buyer undertakes on his own account, even though by agreement with the seller, activities relating to the marketing of the imported goods, the value of these activities is not part of the value of imported goods nor shall such activities result in rejection of the transaction value.

Rule 3(3)

1. Rule 3(3)(a) and rule 3(3)(b) provide different means of establishing the acceptability of a transaction value.
2. Rule 3(3)(a) provides that where the buyer and the seller are related, the circumstances surrounding the sale shall be examined and the transaction value shall be accepted as the value of imported goods provided that the relationship did not influence the price. It is not intended that there should be an examination of the circumstances in all cases where the buyer and the seller are related. Such examination will only be required where there are doubts about the acceptability of the price. Where the proper officer of customs has no doubts about the acceptability of the price, it should be accepted without requesting further information from the importer. For example, the proper officer of customs may have previously examined the relationship, or he may already have detailed information concerning the buyer and the seller, and may already be satisfied from such examination or information that the relationship did not influence the price.
3. Where the proper officer of customs is unable to accept the transaction value without further inquiry, he should give the importer an opportunity to supply such further detailed information as may be necessary to enable him to examine the circumstances surrounding the sale. In this context, the proper officer of customs

should be prepared to examine relevant aspects of the transaction, including the way in which the buyer and seller organize their commercial relations and the way in which the price in question was arrived at, in order to determine whether the relationship influenced the price. Where it can be shown that the buyer and seller, although related under the provisions of rule 2(2), buy from and sell to each other as if they were not related, this would demonstrate that the price had not been influenced by the relationship. As an example of this, if the price had been settled in a manner consistent with the normal pricing practices of the industry in question or with the way the seller settles prices for sales to buyers who are not related to him, this would demonstrate that the price had not been influenced by the relationship. As a further example, where it is shown that the price is adequate to ensure recovery of all costs plus a profit which is representative of the firm's overall profit realized over a representative period of time (e.g. on an annual basis) in sales of goods of the same class or kind, this would demonstrate that the price had not been influenced.

4. Rule 3(3)(b) provides an opportunity for the importer to demonstrate that the transaction value closely approximates to a "test" value previously accepted by the proper officer of customs and is therefore acceptable under the provisions of rule 3. Where a test under rule 3(3)(b) is met, it is not necessary to examine the question of influence under rule 3(3)(a). If the proper officer of customs has already sufficient information to be satisfied, without further detailed inquiries, that one of the tests provided in rule 3(3)(b) has been met, there is no reason for him to require the importer to demonstrate that the test can be met. In rule 3(3)(b) the term "unrelated buyers" means buyers who are not related to the seller in any particular case.

Rule 3(3)(b)

A number of factors must be taken into consideration in determining whether one value "closely approximates" to another value. These factors include the nature of the imported goods, the nature of the industry itself, the season in which the goods are imported, and whether the difference in values is commercially significant. Since these factors may vary from case to case, it would be impossible to apply a uniform standard such as a fixed percentage, in each case. For example, a small difference in value in a case involving one type of goods could be unacceptable while a large difference in a case involving another type of goods might be acceptable in determining whether the transaction value closely approximates to the "test" values set forth in rule 3(3)(b).

Notes to rule 4

1. In applying rule 4, the proper officer of customs shall, wherever possible, use a sale of identical goods at the same commercial level and in substantially the same quantities as the goods being valued. Where no such sale is found, a sale of identical goods that takes place under anyone of the following three conditions may be used:
 - (a) a sale at the same commercial level but in different quantities; or
 - (b) a sale at a different commercial level but in substantially the same quantities;or

- (c) a sale at a different commercial level and in different quantities.
2. Having found a sale under anyone of these three conditions adjustments will then be made, as the case may be, for:
- (a) quantity factors only;
- (b) commercial level factors only; or
- (c) both commercial level and quantity factors.
3. For the purposes of rule 4, the transaction value of identical imported goods means a value, adjusted as provided for in rule 4(1)(b) and (c) and rule 4(2) which has already been accepted under rule 3.
4. A condition for adjustment because of different commercial levels or different quantities is that such adjustment, whether it leads to an increase or a decrease in the value, be made only on the basis of demonstrated evidence that clearly establishes the reasonableness and accuracy of the adjustment, e.g. valid price lists containing prices referring to different levels or different quantities. As an example of this, if the imported goods being valued consist of a shipment of 10 units and the only identical imported goods for which a transaction value exists involved a sale of 500 units, and it is recognised that the seller grants quantity discounts, the required adjustment may be accomplished by resorting to the seller's price list and using that price applicable to a sale of 10 units. This does not require that a sale had to have been made in quantities of 10 as long as the price list has been established as being *bona fide* through sales at other quantities. In the absence of such an objective measure, however, the determination of a value under the provisions of rule 4 is not appropriate.

Note to rule 5

1. In applying rule 5, the proper officer of customs shall, wherever possible, use a sale of similar goods at the same commercial level and in substantially the same quantities as the goods being valued. For the purpose of rule 5, the transaction value of similar imported goods means the value of imported goods, adjusted as provided for in rule 5(2) which has already been accepted under rule 3.
2. All other provisions contained in note to rule 4 shall *mutatis mutandis* also apply in respect of similar goods.

Note to rule 7

1. The term "unit/price at which goods are sold in the greatest aggregate quantity" means the price at which the greatest number of units is sold in sales to persons who are not related to the persons from whom they buy such goods at the first commercial level after importation at which such sales take place.

2. As an example of this, goods are sold from a price list which grants favourable unit prices for purchases made in larger quantities.

Sale quantity	Unit price	Number of sales	Total quantity sold at each price
1-10 units	100	10 sales of 5 units, 5 sales of 3 units	65
11-25 units	95	5 sales of 11 units	55
Over 25 units	90	1 sale of 30 units, 1 sale of 50 units	80

The greatest number of units sold at a price is 80, therefore, the unit price in the greatest aggregate quantity is 90.

3. As another example of this, two sales occur. In the first sale 500 units are sold at a price of 95 currency units each. In the second sale 400 units are sold at a price of 90 currency units each. In this example, the greatest number of units sold at a particular price is 500, therefore, the unit price in the greatest aggregate quantity is 95.
4. A third example would be the following situation where various quantities are sold at various prices.

(a) Sales

Sale quantity	Unit price
40 units	100
30 units	90
15 units	100
50 units	95
25 units	105
35 units	90
5 units	100

(b) Totals

Total quantity sold	Unit price
65	90
50	95
60	100
25	105

In this example, the greatest number of units sold at a particular price is 65, therefore, the unit price in the greatest aggregate quantity is 90.

5. Any sale in India, as described in paragraph 1 above to a person who supplies directly or indirectly free of charge or at reduced cost for use in connection with the production and sale for export of the imported goods any of the elements specified in rule 10(1)(b), should not be taken into account in establishing the unit price for the purposes of rule 7.
6. It should be noted that "profit and general expenses" referred to in rule 7(1) should be taken as a whole. The figure for the purposes of this deduction should be determined on the basis of information supplied by or on behalf of the importer unless his figures are inconsistent with those obtaining in sales in India, of imported goods of the same class or kind. Where the importer's figures are inconsistent with such figures, the amount for profit and general expenses may be based upon relevant information other than that supplied by or on behalf of the importer.
7. The "general expenses" include the direct and indirect costs of marketing the goods in question.
8. Local taxes payable by reason of the sale of the goods for which a deduction is not made under the provisions of rule 7(1)(iii) shall be deducted under the provisions of rule 7(1)(i).
9. In determining either the commissions or the usual profits and general expenses under the provisions of rule 7(1), the question whether certain goods are "of the same class or kind" as other goods must be determined on a case-by-case basis by reference to the circumstances involved. Sales in India, of the narrowest group or range of imported goods of the same class or kind, which includes the goods being valued, for which the necessary information can be provided, should be examined. For the purposes of rule 7 goods of the same class or kind" includes goods imported from the same country as the goods being valued as well as goods imported from other countries.
10. For the purposes of rule 7(2) the "earliest date" shall be the date by which sales of the imported goods or of identical or similar imported, goods are made in sufficient quantity to establish the unit price.

11. Where the method in rule 7(3) is used, deductions made for the value added by further processing shall be based on objective and quantifiable data relating to the cost of such work. Accepted industry formulas, recipes, methods of construction, and other industry practices would form the basis of the calculations.
12. It is recognized that the method of valuation provided for in rule 7(3) would normally not be applicable when, as a result of the further processing, the imported goods lose their identity. However there can be instances where, although the identity of the imported goods is lost, the value added by the processing can be determined accurately without unreasonable difficulty. On the other hand, there can also be instances where the imported goods maintain their identity but form such a minor element in the goods sold in the country of importation that the use of this valuation method would be unjustified. In view of the above, each situation of this type must be considered on a case-by-case basis.

Note to rule 8

1. As a general rule, value of imported goods is determined under these rules on the basis of information readily available in India. In order to determine a computed value, however, it may be necessary to examine the costs of producing the goods being valued and other information which has to be obtained from outside India. Furthermore, in most cases, the producer of the goods will be outside the jurisdiction of the proper officer. The use of the computed value method will generally be limited to those cases where the buyer and seller are related, and the producer is prepared to supply to the proper officer the necessary costings and to provide facilities for any subsequent verification which may be necessary.
2. The "cost or value" referred to in clause (a) of rule 8 is to be determined on the basis of information relating to the production of the goods being valued supplied by or on behalf of the producer. It is to be based upon the commercial accounts of the producer, provided that such accounts are consistent with the generally accepted accounting principles applied in the country where the goods are produced.
3. The "cost or value" shall include the cost of elements specified in clauses (1)(a)(ii) and (1)(a)(iii) of rule 10. It shall also include the value, apportioned as appropriate under the provisions of the relevant note to rule 10, of any element specified in rule 10(1)(b) which has been supplied directly or indirectly by the buyer for use in connection with the production of the imported goods. The value of the elements specified in rule 10(1)(b)(iv) which are undertaken in India shall be included only to the extent that such elements are charged to the producer. It is to be understood that no cost or value of the elements referred to in this paragraph shall be counted twice in determining the computed value.
4. The "amount for profit and general expenses" referred to in clause (b) of rule 8 is to be determined on the basis of information supplied by or on behalf of the producer unless the producer's figures are inconsistent with those usually reflected in sales of goods of the same class or kind as the goods being valued which are made by producers in the country of exportation for export to India.
5. It should be noted in this context that the "amount for profit and general expenses" has to be taken as a whole. It follows that if, in any particular case, producer's profit

figure is low and his general expenses are high, the producer's profit and general expenses taken together may nevertheless be consistent with that usually reflected in sales of goods of the same class or kind. Such a situation might occur, for example, if a product were being launched in India and the producer accepted a nil or low profit to offset high general expenses associated with the launch. Where the producer can demonstrate a low profit on his sales of the imported goods because of particular commercial circumstances, his actual profit figures should be taken into account provided that he has valid commercial reasons to justify them and his pricing policy reflects usual pricing policies in the branch of industry concerned. Such a situation might occur for example, where producers have been forced to lower prices temporarily because of an unforeseeable drop in demand, or where they sell goods to complement a range of goods being produced in India and accept a low profit to maintain competitiveness. Where the producer's own figures for profit and general expenses are not consistent with those usually reflected in sales of goods of the same class or kind as the goods being valued which are made by producers in the country of exportation for export to India, the amount for profit and general expenses may be based upon relevant information other than that supplied by or on behalf of the producer of the goods.

6. The "general expenses" referred to in clause (b) of rule 8 covers the direct and indirect costs of producing and selling the goods for export which are not included under clause (a) of rule 8.
7. Whether certain goods are "of the same class or kind" as other goods must be determined on a case-by-case basis with reference to the circumstances involved. In determining the usual profits and general expenses under the provisions of rule 8, sales for export to India of the narrowest group or range of goods, which includes the goods being valued, for which the necessary information can be provided, should be examined. For the purposes of rule 8 "goods of the same class or kind" must be from the same country as the goods being valued.

Note to rule 9

1. Value of imported goods determined under the provisions of rule 9 should to the greatest extent possible, be based on previously determined customs values.
2. The methods of valuation to be employed under rule 9 may be those laid down in rules 3 to 8, inclusive, but a reasonable flexibility in the application of such methods would be in conformity with the aims and provisions of rule 9.
3. Some examples of reasonable flexibility are as follows:
 - (a) Identical goods. - The requirement that the identical goods should be imported at or about the same time as the goods being valued could be flexibly interpreted; identical imported goods produced in a country other than the country of exportation of the goods being valued could be the basis for customs valuation; customs values of identical imported goods already determined under the provisions of rules 7 and 8 could be used.

(b) Similar goods. - The requirement that the similar goods should be imported at or about the same time as the goods being valued could be flexibly interpreted; similar imported goods produced in a country other than the country of exportation of the goods being valued could be the basis for customs valuation; customs values of similar imported goods already determined under the provisions of rules 7 and 8 could be used.

(c) Deductive method. - The requirement that the goods shall have been sold in the "condition as imported" in rule 7(1) could be flexibly interpreted; the ninety days requirement could be administered flexibly.

Note to rule 10

In rule 10(1)(a)(i), the term "buying commissions" means fees paid by an importer to his agent for the service of representing him abroad in the purchase of the goods being valued.

Rule 10(1)(b)(ii)

1. There are two factors involved in the apportionment of the elements specified in rule 10(1)(b)(ii) to the imported goods - the value of the element itself and the way in which that value is to be apportioned to the imported goods. The apportionment of these elements should be made in a reasonable manner appropriate to the circumstances and in accordance with generally accepted accounting principles.
2. Concerning the value of the element, if the importer acquires the element from a seller not related to him at a given cost, the value of the element is that cost. If the element was produced by the importer or by a person related to him, its value would be the cost of producing it. If the element had been previously used by the importer, regardless of whether it had been acquired or produced by such importer, the original cost of acquisition or production would have to be adjusted downward to reflect its use in order to arrive at the value of the element.
3. Once a value has been determined for the element it is necessary to apportion that value to the imported goods. Various possibilities exist. For example, the value might be apportioned to the first shipment if the importer wishes to pay duty on the entire value at one time. As another example, the importer may request that the value be apportioned over the number of units produced up to the time of the first shipment. As a further example, he may request that the value be apportioned over the entire anticipated production where contracts or firm commitments exist for that production. The method of apportionment used will depend upon the documentation provided by the importer.
4. As an illustration of the above, an importer provides the producer with a mould to be used in the production of the imported goods and contracts with him to buy 10000 units. By the time of arrival of the first shipment of 1000 units, the producer has already produced 4,000 units. The importer may request the proper officer of customs to apportion the value of the mould over 1,000 units, 4,000 units or 10,000 units.

Rule 10(l)(b)(iv)

1. Additions for the elements specified in rule 10(l)(b)(iv) should be based on objective and quantifiable data. In order to minimise the burden for both the importer and proper officer of customs in determining the values to be added, data readily available in the buyer's commercial record system should be used in so far as possible.
2. For those elements supplied by the buyer which were purchased or leased by the buyer, the addition would be the cost of the purchase or the lease. No addition shall be made for those elements available in the public domain, other than the cost of obtaining copies of them.
3. The case with which it may be possible to calculate the values to be added will depend on a particular firm's structure and management practice, as well as its accounting methods.
4. For example, it is possible that a firm which imports a variety of products from several countries maintains the records of its design centre outside the country of importation in such a way as to show accurately the costs attributable to a given product. In such cases, a direct adjustment may appropriately be made under the provisions of rule 10.
5. In another case, a firm may carry the cost of the design centre outside the country of importation as a general overhead expense without allocation to specific products. In this instance, an appropriate adjustment could be made under the provisions of rule 10 with respect to the imported goods by apportioning total design centre costs over total production benefiting from the design centre and adding such apportioned cost on a unit basis to imports.
6. Variations in the above circumstances will, of course, require different factors to be considered in determining the proper method of allocation.
7. In cases where the production of the element in question involves a number of countries and over a period of time, the adjustment should be limited to the value actually added to that element outside the country of importation.

Rule 10(l)(c)

1. The royalties and licence fees referred to in rule 10(l)(c) may include among other things, payments in respect to patents, trademarks and copyrights. However, the charges for the right to reproduce the imported goods in the country of importation shall not be added to the price actually paid or payable for the imported goods in determining the customs value.
2. Payments made by the buyer for the right to distribute or resell the imported goods shall not be added to the price actually paid or payable for the imported goods if such payments are not a condition of the sale for export to the country of importation of the imported goods.

Rule 10(3)

Where objective and quantifiable data do not exist with regard to the additions required to be made under the provisions of rule 10, the transaction value cannot be determined under the provisions of rule 3. As an illustration of this, a royalty is paid on the basis of the price in a sale in the importing country of a litre of a particular product that was imported by the kilogram and made up into a solution after importation. If the royalty is based partially on the imported goods and partially on other factors, which have nothing to do with the imported goods (such as when the imported goods are mixed with domestic ingredients and are no longer separately identifiable, or when the royalty cannot be distinguished from special financial arrangements between the buyer and the seller), it would be inappropriate to attempt to make an addition for the royalty. However, if the amount of this royalty is based only on the imported goods and can be readily quantified, an addition to the price actually paid or payable can be made.

[F. No. 467/35/2007-Cus. V]

ASEEM KUMAR, Under Secy.